मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर रहा हूं। आप कृपा करके इस चीज को देखें जो अडवाणी जी ने कही है। आज सुबह मेरे पास आदमी आए थे। उन्होंने कहा कि हमारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Order please. I do not allow any discussion.

Shri Nawal Kishore

श्री राजनारायण : मैं आपका ध्यान अडवाणी जी की इन बातों की ओर दिला रहा हूं। . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री वी०बी० राजू): आप मेहरबानी करके चेयर की कद्र कीजिए।

श्री राजनारायण: मैं आपकी बिल्कुल कद्र कर रहा हूं। आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): I am not allowing anybody No discussion.

श्री गुणानन्द ठाकुर: मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा आप मुझे इजाजत दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Please bear in mind I have allowed Mr. Advani to raise the point and nothing more.

(*Interruptions*)

श्री राजनारायण: जो यूथ कांग्रेस बनाई गयी है वह लेबर को तंग करने के लिए बनाई गई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को कहें कि वह उनकी हिफाजत करें। क्योंकि अगर रेल मजदूरों की औरतों की हिफाजत नहीं होगी तो हमारे राष्ट्र की हिफाजत नहीं होगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): No, please. First obey the Chair. I am not going to allow it Shri Nawal Kishore.

---

1. THE UNION DUTIES OF EXCISE (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL, 1974.

2. THE ADDITIONAL DUTIES OF EXCISE (GOODS OF SPECIAL IMPORTANCE) AMENDMENT BILL, 1974.

3. THE ESTATE DUTY (DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL, 1974— *contd.*

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो तीन विधेयक वित्त मंत्री जी ने पेश किए इनका दायरा बहुत सीमित है। इनका सबंध केवल यहां तक है कि छठे वित्त कमिशन ने जो सिफारिशें की हैं कि एक्साइज ड्यूटी से, एस्टेट ड्यूटी से या एडीशनल एक्साइज ड्यूटी से जो धन इकट्ठा होता है उसका बटवारा विभिन्न राज्यों के बीच कैसे हो। इसलिए मान्यवर मैं कोशिश करूंगा कि अपने आपको वहीं तक सीमित रखूं और टैक्सेशन की पालिसी में नहीं जाऊं।

मैंने यह देखा है कि तीसरे फाइनेंस कमिशन से लगातार 3,4,5,6 तक कि उनकी एक सी सिफारिश है कि एक्साइज ड्यूटी से जो पैसा इकट्ठा होता है उसका 20 परसैन्ट स्टेट को दिया जाए। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह एक बात तय हो गयी तो क्यों हर पांच साल के बाद फाइनेंस कमिशन बैठाया जाए और उसको इस बात की तकलीफ दी जाए कि वह हर बार उसी बात की रिपोर्ट करे। क्या यह मुमकिन नहीं है कि एक दफा जो परसन्ट फिक्स हो जाए, 20,25,30 परसैन्ट उसी के हिसाब से जो पैसा निकलता है वह स्टेट में बांट दिया जाए। मैं यह नहीं समझ पाया कि 20 परसैन्ट की सैन्टिटी क्या है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो धन बांटा जाता है स्टेट में उसका सारा अधिकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। जब फैडरल स्ट्रक्चर बना था उस वक्त यह तय हुआ था कि जो स्टेट आटानामि है उसको महफूज रखा जाएगा। स्टेट और सेन्टर के सबंध करीब-करीब बराबरी के होंगे, कुछ विषयों को छोड़कर, जिसमें केवल केन्द्र को अधिकार होगा कि वह उसके बारे में निर्णय ले, उसके सबंध में कानून बनाए। मैं यह देखता हूं कि अहिस्ता-अहिस्ता स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल आश्रित होती जा रही है केन्द्र के ऊपर और केन्द्र इस बात को तय करता है कि उनका काम काज कैसे चलाए, उनकी अर्थ-व्यवस्था किस प्रकार चलाए।

[श्री नवल किशोर]

मुझे याद है मैंने अखबारों में पढ़ा कि जब उड़ीसा में चुनाव चल रहे थे या होने वाले थे तो कुछ नेताओं ने, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, इस प्रकार के भाषण दिए कि अमुक पार्टी को वोट देने से केन्द्र से सहायता अधिक मिलेगी। मैं जानना चाहूंगा कि वह सही है या गलत। लेकिन अगर सही है तो एक बड़ा बुनियादी सवाल सामने खड़ा होता है कि केन्द्रीय सरकार के हाथ में एक ऐसी शक्ति हो गई जिससे वह वोटर्स को अपनी तरफ मूव कर सकता है और जो डेमोक्रेटिक सैट-अप है उसके साथ खिलवाड़ कर सकता है। उत्तर प्रदेश में, मैं नहीं कहता कि कोई गलत बात हुई या नहीं हुई। इत्तफाक से जितने प्रोजेक्ट्स थे उन सब को कोल्ड स्टोरेज में रखा गया और चुनाव के टाइम में ही उन सबका फाउन्डेशन स्टोन रखा गया। मैं केवल ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो एक आर्थिक शक्ति केन्द्र के हाथ में है यह अहिस्ता अहिस्ता प्राविशल आटानामी को इरोड करती जा रही है, उसको कमजोर करती जा रही है और यही वजह है कि आज तामिलनाडु के मुख्य मंत्री ने ग्रेटर प्राविशल आटानामी की बात उठाई है हालांकि मैं उससे इत्तिफाक नहीं करता हूं। वे जिस बात को चलाना चाहते है उससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन मजबूरन इस तरह की मांग उठेगी अगर इसी तरह कोई न कोई अंकुश या आर्थिक नियन्त्रण ज्यों ज्यों आपकी तरफ से बढ़ता जाएगा और ज्यों ज्यों काफी चीजों में आपकी मदाखलत बढ़ती जाएगी। श्रीमन्, इस कमीशन ने कुछ अच्छी बातें भी कही है। एक तो उन्होंने वही कह दिया जैसा मैंने कहा 20 परसेंट पर तो कोई चेंज नहीं। एक बात उन्होंने जरूर कही :

"The Commission had, however, recommended that the auxiliary duties of excise introduced from 1973-74 which were not shareable with the States at present should also be shared with the States as in the case of basic Union Excise Duties from 1976-77."

मैं वित्त मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि आग्जीलरी एक्साइज ड्यूटीज है उनमें और एक्साइज ड्यूटीज में क्या फर्क है ? क्या केवल नामिनक्लेचर का फर्क है ? यह आपने बताया नहीं है। एक्साइज ड्यूटी होती तो स्टेटस को खुद व खुद हक हो जाता और वे अपना शेयर मांगतीं। लेकिन नामेनक्लेचर बदल कर आपने उनको शेयर से वंचित किया। अब आपने अहसान दिखा दिया कि कमीशन की रिकमण्डेशन है, आपको कुछ हिस्सा दे दिया जाएगा।

आपका एस्टीमेट है, 900 करोड़ रु० से अधिक 1974 से 1979 तक का है इन फाइव ईयर्स में स्टेटस को बांटने का और साथ ही साथ यह पैसा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि हर साल और एडिशनल टैक्सेज बजट के साथ आएंगे जैसा कि इस साल 212 करोड़ रु० टैक्सेज के आ गए। मगर जिस रफ्तार से पैसे की कीमत घट रही है और जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही है हर चीज की, उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो जो पैसा आप आगे देंगे भी या देना होगा उसको अगर हम आने वाली कीमतों के हिसाब से जोड़ें तो मुझे शक है कि जब आज रुपये कि कीमत 30.8 परसेंट हो गई है तो यह जो सहायता है यह काफी नहीं होगी। आज एक बहुत बड़ा सवाल है स्टेट्स के सामने कि उनके यहां डेफिशिट होता है। आपने यह नियम बनाया था कि हम ओवरड्राफ्ट को रोकेंगे और कोशिश करेंगे कि ओवरड्राफ्ट न हो। केरल में एक स्थिति पैदा हुई कि उनके चेक्स को रिजर्व बैंक ने इन्कार कर दिया कि कैश नहीं करेंगे और इससे वहां पर हलचल पैदा हुई। मिस्टर कुरियन ने भी केरल स्टेट की बात यहां उठाई। तो दिक्कत यह है कि एक तरफ तो डेफिशिट करने की आपको छूट है, आप जितना चाहें डेफिशिट करते जाइए, आपको कोई चेक् करने वाला है नहीं लेकिन आपकी हर नीति का असर पड़ता है स्टेट्स पर। एक जमाने में मांग है कि स्टेट के इम्प्लाईज की तनख्वाह और सेन्टर के इम्प्लाईयीज की तनख्वाह में कोई पैरिटी होनी चाहिए। आज उसी बात को लेकर यह मांग है—हमारे जो रेलवेज के इम्प्लायीज है उनकी मांग है कि हमारी तनख्वाह में और पब्लिक अंडरटेकिंग की तनख्वाह में पैरिटी होनी चाहिए। मैं श्रीमन् एक बात समझ नहीं पाया कि अगर लखनऊ में एक दफ्तर स्टेट गवर्नमेंट का है वहां चपरासी की एक तनख्वाह है और अगर वहीं सेन्ट्रल गवर्नमेंट का दफ्तर है तो वहां के चपरासी की दूसरी तनख्वाह है। मैं यह बात मान सकता हूं कि दिल्ली का स्टैंडर्ड कुछ ऊंचा हो, बम्बई का स्टैंडर्ड कुछ ऊंचा हो, कलकत्ता का स्टैंडर्ड कुछ ऊंचा हो, मगर एक ही शहर में एक ही जाब के लिए 2 तनख्वाह हों, यह बात मुनासिब नहीं है। आपने

पे कमीशन की रिकमंडेशंस मान ली और कल आपका फेडरेशन आफ गवर्नमेंट इम्प्लायीज एण्ड वर्कर्स जो है, उसके भी लोग हड़ताल में चले गए। कई सौ करोड़ रु० का बोझ सेन्ट्रल एक्सचेकर के ऊपर पे कमीशन की सिफारिश लागू करने के बाद पड़ चुका है और चव्हाण साहब ने कहा है कि 61 करोड़ रु० हमने रिकरिंग और 25 करोड़ रु० नान रिकरिंग पे कमीशन की रिकमंडेशन के अलावा दिया है, अन्य बेनिफिट्स के अंदर। नतीजा क्या होना है? इसका इफेक्ट पड़ता है स्टेट्स के ऊपर वहां के इम्प्लायीज कहते है आपने सेन्ट्रल गवर्नमेंट वालों का इतना बढ़ा दिया, हमारी भी बढ़ा दीजिए। श्रीमन् जब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बढ़ता जाता है तो स्टेट के अंदर डेफिशिट भी बढ़ता जाता है और डेवलपमेंट बढ़ता जाता है तो एस्टेट के अंदर डेफिशिट भी बढ़ता जाता है और डेवलमेंट की गुंजाइश नहीं रहती। तो जब डेवलमेंट की गुंजाइश नहीं रहती तो फिर स्टेट बेकवर्ड होती चली जा रही है। मैं आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से इस विचार का हूं कि मान लीजिए यहां पर फैडरल स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट नहीं होती, यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट होती, तो सारे हिन्दुस्तान के कर्मचारियों की जिम्मेदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होती। लेकिन आजकल हालत यह है कि डेवलमेंट के सारे काम स्टेटों में होते है मगर पैसा सारा केन्द्र के हाथ में रहता है। इसलिए एक बात सोचने की है कि जब यहां पर सेन्टर में तनख्वाह बढ़ती है तो उसका असर स्टेटों में भी पड़ता है और इस जिम्मेदारी को सेन्टर को अपने ऊपर लेना चाहिए क्योंकि डेवलमेंट के जितने भी काम है, वे आप देखेंगे कि स्टेटों के हाथों पर है। तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट एक माने में केवल सुपरवाइजरी गवर्नमेंट है।

श्रीमन्, हम यह देखते है कि देहली के अन्दर आजकल 12-14-20 मंजिले ईमारतें बन रही है और बनती ही चली जा रही है। यहां पर बिल्डिंग बहुत बनती है। हमारे श्री ओम् मेहता हाउसिंग मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है। जब यहां पर इस तरह की बिल्डिंगें बनती है तो स्टेटों में भी इस तरह का कम्पीटिशन होता है। इस तरह से यहां पर एक तरफ तो सरकारी फाइनेंस से अट्टालिकाएं बनाई जा रही है। दूसरी तरफ स्टेट्स में आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे रीजनल इम्बेलेंसेज हो जाता है। मैं समझता हूं कि फाइनेंस कमिशन का यह भी काम है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है, जो डिस्पैरिटी है, उसको दूर करने की कोशिश की जाय। उन्होंने कुछ जबानी हमदर्दी की तो है। उन्होंने यह कहा है कि जो एक्साइज ड्यूटी है, उसका जो पैसा आयेगा, उनमें से 75 प्रतिशत आबादी के हिसाब से और 25 प्रतिशत बैकवर्डनेस के हिसाब से दिया जायेगा।

श्रीमन्, मै उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि वह भारत का हृदय हैं। श्रीमन्, बड़ी बड़ी मीठी बाते हम से की जाती है। हमें बड़े मुगालते में रखा जाता है। हमें इस बात की खुशी है कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ, तब से हिन्दुस्तान के लिए प्रधान मंत्री हमने ही दिया है। मगर जब हम अपने यहां की हालत देखते है तो दुख होता है। मुझे इस बात की अच्छी तरह से याद है कि पिछले उत्तर प्रदेश से बहुत मिनिस्टर यहां पर हुआ करते थे। जब मैं मिनिस्टर था तो मैं दिल्ली आया था और मैंने यहां शिकायत की कि यू० पी० को सेन्ट्रल प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया जाता है? एक, दो प्लान बीत गये है, मै यहां पर किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वे साउथ के थे, तो उन्होंने कहा कि या तो प्रोजेक्ट ले लो या फिर मिनिस्टर ले लो। (Interruption) इस तरह से एक, दो, तीन प्लान खत्म हो गये।

श्री एन० जी० गोरे. प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बहुत सी चीजों का उद्घाटन पिछली दफा किया था।

श्री नवल किशोर. हर चीज का उद्घाटन होता है और उसका अन्त भी होता है। ये उद्घाटन हो गये और उनका वहीं काम भी खत्म हो गया क्योंकि उद्घाटन का एक परपज था और वह परपज अब खत्म हो गया। श्रीमन्, जो बात मै कह रहा था वह मै ईस्टर्न यू० पी० के संबन्ध में कहना चाहता हूं। उसकी हालत बिहार से भी खराब है। वहां कुछ इलाके ऐसे है जिनकी हालत कतई अच्छी नहीं है। श्रीमन्, आपको यह बात सुनकर ताज्जुब होगा कि आजादी के 27 साल बाद भी पहाड़ो में कुछ इलाके ऐसे है जहां माताओं और बहिनों को पानी लेने के लिए चार या पांच मील जाना पड़ता है। मिर्जापुर के अन्दर पानी नहीं है। हमारे मंत्री जी के फादर का घर इलाहाबाद में

[श्री नवल किशोर]

है वही मेजा का क्षेत्र है, यह एक तहसील है और वहा पर आज भी पानी की तकलीफ है, मिर्जापुर मे भी यही स्थिति है। तो मै यह कहना चाहता हू कि आज ऐसी ही स्थिति के कारण पहाड में मायूसी की वजह से इस बात की मांग की जा रही है कि हमारा एक अलग से राज्य बनाया जाय। श्रीमान्, आजकल राज्य बनाने का बडा भारी शोर है। मै इसके कत्तई खिलाफ हू कि राज्य बांटे जायें जब, श्रीमान् आपके राज्य के बटवारे की बात आई तो मै उसके भी खिलाफ था। यह ठीक है कि अगर यह बात चलती रही और असतुलन बढता गया तो लोग मायूस होकर कहेंगे कि हमको बांट दो, अलग स्टेट बना दो। मै नही समझ पाता हू कि असेंबली के डिस्साल्व करने से कीमतो के घटने का क्या वास्ता है, लेकिन आदमी मायूसी मे कहता है कि असेम्बली को डिसाल्व कर दो, मिनिस्टर इस्तीफा दे और अब यह भी कहते है कि लोक सभा को भग कर दो। मै यह कहना चाहता हू कि जो इम्बैलैसेज है उनको आपको दूर करना पड़ेगा। कमीशन ने सिफारिश की है 75 परसेंट पापुलेशन की। मै इससे इत्तिफाक करता हू और इसलिए इत्तिफाक करता हू कि इस प्रिसिपल की आज से नही जब डा० सम्पूर्णानन्द 54 मे मुख्य मंत्री थे तब से माग की जाती रही है कि पापुलेशन बहुत बडा आधार होना चाहिए केन्द्रीय सहायता के लिए।

इसके साथ साथ एक बात और। जो आपका दूसरा विधेयक है उसमे 56 में स्टेट्स ने वालंटरिली जो उनका कास्टीट्यूशनल अधिकार था कुछ चीजो पर सर्टैक्स लगाने का जैसे शुगर, टुबैको, टैक्सटाइल पर, वह आपको दे दिया। अब मुझको मालूम हुआ है कि कुछ स्टेट्स, जिनमे उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, वैस्ट बंगाल आदि है, यह चाहती है कि वह अधिकार उनको वापस दे दिया जाय। कमीशन का कहना यह है कि जो आय स्टेट्स को सर्टैक्स से होती इस बटवारे मे उससे कम नही होगी। मेरा कहना यह है कि अगर यह बात सही है, तो आप क्यो खामखाह तकलीफ उठा रहे है, उनकी चीज उनको वापिस कर दीजिए, ज्यादा आमदनी हो तो उनकी, कम हो तो उनकी। मेरे दोस्त रणवीर सिह हाथ हिला रहे है। हमारे देश मे ऐसे लोग भी है जो जिस शाख पर बैठे है उसी को काटना शुरू कर देते है। मै आपकी स्टेट की भी अच्छाई की बात कह रहा हू।

तीसरी बात यह है कि 838 करोड़ रुपया दिया गया है Upgradation of Standards of administration and social services in the backward States. आइडिया बहुत अच्छा है और मै इसका स्वागत करता हू। गवर्नमेंट ने तय किया था कि हम कैपिट-लिस्ट्स को कुछ रियायतें देंगे ताकि वे बैकवर्ड एरियाज मे जाकर अपने कारखाने खोले। मुझे पता नही -- आप, श्रीमान, आकडे वाले आदमी है, आपको आकडे ज्यादा याद रहते हैं--कितने कारखाने बैकवर्ड एरियाज मे खोले गए है। मै चाहता हू कि राज्य का जो बैकवर्ड इलाका है उसको इससे फायदा पहुचे। अभी हमारे दोस्त जोशी ने कहा कि ऐसा न हो कि जो ऊचा तबका है उसको फायदा पहुच जाय और गरीब को फायदा न पहुंचे। मुझे बड़ी तकलीफ है कि बावजूद बीस साल के नियोजन के सरकार को यह कहना पड़ा कि अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। देहात में हमने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन किन काश्तकारो को फायदा हुआ ? फायदा उनको हुआ जो बड़े-बड़े जबरदस्त किसान थे जैसे चौधरी रणबीर सिह।

श्री रणवीर सिंह : मै तो आपका मुजारा हूं।

श्री नवल किशोर : ऐसे लोगो को फायदा हुआ, लेकिन जो छोटे किसान थे उनको फायदा नही हुआ। मै यह भी चाहता हूं कि जब सेन्ट्रल गवर्नमैंट 838 करोड रुपया दे तो यह भी देखे कि यह पैसा सही माने मे उन स्टेट्स का जो पिछडा हुआ क्षेत्र है उस पर खर्च हो (time bell rings) कमीशन ने यह भी कहा कि ऐसा मैकेनिज्म ईवाल्व होना चाहिए कि जो पैसा हम देते है वह पैसा उसी के ऊपर खर्च होगा।

आपने डेट रिलीफ के लिए कुछ पैसा दिया है। जहां तक पैसा देने की बात है मै उसे बहुत अच्छा मानता हू, लेकिन देखने की बात यह है कि कौन सा मैकेनिज्म निकाला है आपने जिस के आधार पर हम यह कह सके कि पैसे का इस्तेमाल सही होगा। दो बाते कह कर मै खत्म करता हू।

प्लान एक्सपेंडीचर और नान-प्लान एक्सपेंडीचर के लिए अलोकेशन आप करते है। मैं यह भी चाहता हू कि स्टेट्स की क्या रिसोर्सेज है, क्या उनकी प्राबलम्स

है, इन सबको भी देखना चाहिए और बेहतर हो कि प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन ये दोनों का आपस में एक ज्वाइंट कमल्टेशन हो। मंत्री महोदय ने कहा कि मिस्टर मिन्हास जो प्लानिंग कमीशन के मैम्बर थे वह फाइनेंस कमीशन के भी मैम्बर थे। वह तो एक कामन आदमी हो गये। मगर दोनों कमीशनों के बीच में क्या लायेजा है, वह बात मुझे साफ नहीं हुई।

आखरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अकसर ड्यूटीज में इरोजन होता है और पैसा वसूल नहीं होता है और जितना पैसा कम वसूल होगा उतनी ही स्टेटस की रिसोर्सेज कम होंगी। मैं यह भी चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात की तरफ देखें कि ड्यूटीज ठीक तरह से वसूल हों क्योंकि उसके अन्दर जो भ्रष्टाचार होता है उससे मोटे मोटे लोगों से पैसा वसूल नहीं होता है।

श्रीमान, इन्हीं शब्दों के साथ, जहां तक ये तीन विधेयक है, उनका मैं समर्थन करता हूं। शायद आप यह बात जानते ही है कि जो विधेयक उप मंत्री महोदया पेश करती है उनका मैं समर्थन कर ही देता हूं। धन्यवाद।

श्री रणधीर सिंह (हरियाणा) : उप-सभापति जी, मैं सघीय उत्पादन शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1974, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक, 1974 तथा सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1974 का समर्थन करता हूं।

जहां मैं इन विधेयकों का समर्थन करता हूं वहां यह मानता हूं कि हमारे छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए ये विधेयक लाये गये। मुझे खुशी है और आप भी जानते हैं कि जो हमारे वित्त आयोग के सभापति रहे—ऐसे दो सदस्य इस सदन के है—श्री महावीर त्यागी और श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी साहब। मुझे यह भी खुशी है कि वह पहले मुख्य मंत्री हैं उनको वित्त आयोग का सभापति बनाया गया और इसीलिए उनकी सिफारिशें पहले के मुकाबले में कुछ अच्छी है।

आप जानते हैं कि जब हमारे देश के अन्दर संविधान बना तो कर लगाने की शक्ति का भी बटवारा हुआ। केन्द्र को कर लगाने की जो शक्ति मिली और प्रदेशों को कर लगाने की जो शक्ति मिली उनमें थोड़ा सा फर्क रहा। केन्द्र को जो कर लगाने की शक्ति मिली वह ऐसी चीजों पर कर लगाने की शक्तियां थी जिनसे आय आसानी से बढ़ सकती थी और जो प्रदेशों को शक्ति मिली वह ऐसे हिस्सों पर कर लगाने की शक्ति मिली जिनकी आमदनी आसानी से बढ़ नहीं सकती। इसीलिए 1950-51 तथा 1972-73 के आंकड़े अगर देखे जाये तो प्रदेशों की भी करों की आमदनी बढ़ी वह नौ गुनी बढ़ी 1950-51 में और केन्द्र की करों की जो आमदनी बढ़ी वह 11 गुनी बढ़ी इसके साथ साथ जहां खर्च का सबध है, आप जानते हैं कि देश के आम आदमी के लिए जो खर्च करने की जिम्मेदारी है वह प्रदेशों के हिस्से में आई चाहे शिक्षा हो, चाहे गावों में पानी का इंतजाम हो, नहरों का इंतजाम हो, चाहे उनकी स्वास्थ्य सेवा का इंतजाम हो। देश की आजादी के बाद लोगों की सुख शांति के लिए जितने काम करने थे उन सब पर खर्च करने की जिम्मेदारी प्रदेशों की आई। जहां केन्द्रीय सरकार को कर लगाने की शक्ति प्रदेशों के मुकाबले में ज्यादा है उस के साथ साथ केन्द्रीय सरकार के पास रिजर्व बैंक भी है, जो रुपया छापता है और जहां से रुपया बनता है और बैंकस भी है। तो रुपये के मामले में ज्यादा अख्तियार केन्द्र के पास है और करों की आमदनी भी ज्यादा केन्द्र के पास है। मैं उन सदस्यों में से नहीं हूं कि जो केन्द्र को कमजोर करना चाहते है। मैं मानता हूं कि आर्थिक तौर पर भी और शक्ति के तौर पर भी अगर देश का केन्द्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, लेकिन प्रदेशों की तरक्की के लिए आज जो जरूरत है वह केन्द्र को पूरी करनी चाहिए और इसीलिए आर्थिक नीति में जो लचीलापन करने की आवश्यकता है वह उसे करनी चाहिए। आप जानते हैं कि रेड्डी साहब के वित्त आयोग ने एक और सिफारिश की है कि 1967 करोड़ रुपया जो इन पांच साल में प्रदेशों को कर्ज देना लाजमी था, उन के फैसले के मुताबिक उस कर्ज को आगे इन पांच सालों में प्रदेशों से न लिया जाये। उन्होंने यह सिफारिश भी की है और सरकार ने उसे कबूल भी किया है, लेकिन खास तौर पर वित्त मंत्रालय को जिस बात पर सोचना चाहिए वह यह है कि यह प्रदेश की सरकारें क्यों अपना कर्जा अदा नहीं कर सकी? क्यों नहीं अपना ब्याज अदा कर सकी। आज हालत यह है कि हिन्दुस्तान के जो बहुत सारे बिजली बोर्ड है विभिन्न प्रदेशों में वह अपने कर्ज का ब्याज भी नहीं दे पा रहे है।

[श्री रणबीर सिंह]

कोई साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया उन को ब्याज अदा करना हैं। जो कर्ज दिया गया है उन को आप उनसे वापस नहीं ले सकते और उस की अदायगी की जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकारों की है। उस का नतीजा साफ है। यही बात नहरों की है। नहरों पर जो रुपया खर्च हुआ वह प्रदेश की सरकारों को खर्च करना पड़ता है और उस में डेढ़ सौ करोड़ के करीब उन को एक साल में घाटा पड़ता है। वह इन पर टैक्स बढ़ा सकते है या नहीं, बिजली बोर्ड अपनी आमदनी बढ़ा सकते है या नहीं, यह भी सोचने की बात है, एक विषय है, लेकिन उस के साथ साथ हमे यह भी सोचना होगा कि आखिर जो नहरें बनी वह तो देश की है, देश की दौलत हैं, वह देश के लिए अनाज पैदा कराती है, जो बिजली बोर्ड है वह देश के लिए बिजली पैदा करते है और देश के अंदर बिजली होगी तो देश के कारखानों की आमदनी बढ़ेगी और वह अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। तो इस लायक हम उन को कर रहे है या नहीं कर रहे है यह हम को सोचना है। उपसभाध्यक्ष जी, भाखड़ा डैम पर पहली योजना के पहले काम शुरू हुआ था और उस पर कर्ज और ब्याज जो था, ढाई और पौने तीन परसेंट पर उस का ब्याज था, वह पंजाब और हरियाणा ने अदा किया, कर्ज को भी और ब्याज को भी, लेकिन अब आप देखें कि राजस्थान है उसकी नहर के लिए ढाई सौ करोड़ रुपया दिया जा चुका है, न वह उस का ब्याज अदा कर सकेंगे और न ही वह उस कर्ज को वापस कर सकेंगे हम अपने खाते में लिखते रहें कि उस को अदा किया जायेगा और वह उस को टालते रहे यह कोई अच्छी नीति नहीं है। नीति हम को ठीक तौर पर जहां बदलने की आवश्यकता है, बदलनी चाहिये। मैं आप से निवेदन कर रहा था कि आज जरूरत इस बात की है कि देश के अन्दर सब से ज्यादा दो चीजों की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए—एक बिजली की पैदावार यानी बिजली को पैदा करने की क्षमता बढ़े, दूसरे देश के अन्दर अनाज बढ़े और दोनों का संबध बिजली और सिंचाई से है। बिजली और सिंचाई के लिए हम किस सूद पर कर्जा देते है और किस को? किसी साहूकार को नहीं, किसी कारखानेदार को नहीं, कर्जा देते हैं सरकार को। मैं उपसभाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर देश में हम बिजली बढ़ाना चाहते है जैसा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्दर हमारा लक्ष्य है 165 मिलियन यूनिट्स की क्षमता और बढ़े और हम यह चाहते है कि इस मे हम कामयाब हों तो हमें अपनी नीति मे तब्दीली लानी होगी। हम कारपोरेशन बनायें हर प्रदेश के अन्दर, बिजली पैदा करने के लिए, और उन को सस्ते ब्याज पर कर्जा दिया जाए। मैं मानता हूं कि जैसे अमरीका एक देश है, अमरीका के अन्दर नहर पर जो पैसा लगाया जाता है उस का ब्याज नहीं लिया जाता, लेकिन हमारा देश कृषिप्रधान देश है। यहां उस पर ब्याज लिया जाता है 5, 6 परसेंट और नतीजा यह हो रहा है कि अनाज महंगा हो गया है।

श्री श्यामलाल यादव. मान्यवर, एक बात बताइये कि आखिर यह बात किस को कह रहे है कि ज्यादा ब्याज लेते है।

श्री ओम् मेहता. कांग्रेस से ही कह रहे है।

श्री रणबीर सिंह माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते है, इन्हें भी मिनिस्टर बनने का मौका मिला है और मुझे भी मिला है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू): कौन कामयाब रहा ?

श्री रणबीर सिंह: कामयाब तो मैं ही रहा।

दूसरी बात यह है कि प्रजातंत्र की प्रणाली में, समदीय प्रणाली मे कोई तरीका बदलने के लिए किसी सरकार के लिए आसान नहीं होता उसे एक वायुमंडल तैयार करना होता है। मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह मेरे साथ सहमत हैं तो इस वायुमंडल को बदलने की कोशिश करें। अगर माननीय सदस्य मानते है कि यह बात सही है तो उन को भी इस बात का स्वागत करना चाहिए। सरकार वही करेगी जो पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट के ज्यादा सदस्य जिस तरफ कहेंगे उस तरफ सरकार को चलना होगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि अमरीका के अन्दर नहरों के ऊपर जो सरमाया लगाया जाता है उसका ब्याज नहीं लिया जाता और यहां हालत यह है कि 5-6 परसैंट ब्याज लिया जाता है। इस तरह से बिजली का बोर्ड पांचवी योजना के अन्त तक एक हजार करोड़ रुपये तक ब्याज अदा नहीं कर सकेगा वह और जितना

सरमाया अभी तक लगा हुआ है वह सब इकट्ठा हो जायेगा इस पाचवी योजना के अंत तक। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर गम्भीरता से विचार किया जाए और गम्भीरता से विचार करके आर्थिक नीति मे तबदीली की जाए।

जहां तक नहरों और बिजली का सबध है उसमें या तो ब्याज न लिया जाए और अगर लिया जाए तो मामूली ब्याज लिया जाए। दूसरे जो कर्ज देते है वह कर्ज वापस भी न लिया जाए। क्योंकि कर्ज का रुपया जो है वह ठीक तरह से खर्च हुआ है। भिलाई के कारखाने की जो हमारी कैपिटल है उसको हम वापस न ले और दूसरे सरकारी कारखानों मे जो सरमाया लगता है उसको भी वापस न ले। नहरो मे बिजली पैदा करने के लिए जो सरमाया लगाया जाता है उसको भी वापस लेने की न सोचें। अगर वह सोचते हैं तो सही नहीं है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी: अभी एक प्रश्न इन्होंने किया है कि कर्ज जो दिया जाए उसको वापस न लिया जाए। मै यह पूछ रही थी कि जो कर्ज दिया गया है अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो वह कर्ज कहलाएगा या नही ?

श्री रणबीर सिंह उपसभाध्यक्ष जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरफ मैं आना चाहता था उस तरफ मेरा ध्यान दिलाया। आप जानती है, आज हिन्दुस्तान के अदर हमारा रिजर्व बैंक नोट छापता है और रुपया, सेक्योरिटी, गिल्ट ...

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू): आपका टाइम हो रहा है। बहुत बड़े पाइन्ट पर मत जाइये।

श्री श्यामलाल यादव: अब कोई सेक्योरिटी नही है।

श्री रणबीर सिंह: चूंकि वित्त मंत्री महोदया ने एक प्रश्न उठाया, मुझे जबाव देने का मौका देना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि रिजर्व बैंक नोट छापे, जो हमारी तरक्की के काम होते हैं उस सेक्योरिटी पर नोट छापे--- इतना कर्ज देना है, इतना लेना है, इसकी जो वर्किंग एक्सपेंसेज है वह लोंगो से या प्रदेशो से लिया जाए, डेप्रिसिएशन भी आ सकता है, ब्याज भी आ सकता है, दूसरे वर्किंग एक्सपेंसेज भी आ सकते हैं। तो मै निवेदन कर रहा था कि हमारे रिजर्व बैंक के अन्दर की नीति भी बदलनी चाहिए और हम समाजवाद लाना चाहते है, फिक्र रहती है नोट ज्यादा छप गए, कम छप गये, हमको तो सबको काम देना है। मै समझ सकता हूं कि जो आदमी व्हाइट कालर है उनको कम करे, जो पैदा नही करते। वह पैसा कम खर्च किया जाये। लेकिन जो देश के लिए सड़क बनाए, देश के लिए नहरे बनाये, देश की तरक्की के लिए और काम करे और चूंकि बेकारी है, उन सब को काम देना चाहिए---वह सरकार की जिम्मेदारी है, तो मै जहा इस विधेयक का समर्थन करता हू इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। मैं 2 मिनट लेना चाहता हू ....

उपसभाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजू) बस आखरी पाईन्ट बोल दीजिए।

श्री रणबीर सिंह: अभी मेरे साथी ने जिक्र किया जूट ग्रोअर्स को बहुत तकलीफ है, और जो कई प्रदेश है---कोई चाय पैदा करता है, कोई काफी पैदा करता है, कोई पटसन पैदा करता है, कुछ अनाज पैदा करते है, और जो प्रदेश अनाज पैदा करते है जो प्रदेश आज देश को अनाज खिलाते है---पैजाब है, हरियाणा है, वैस्टर्न यू० पी० है, आपका आन्ध्र प्रदेश है और दूसरे प्रदेश है---वे अपनी आमदनी नही बढ़ाते। मैने देखा कास्टीट्यूशन का जो आर्टिकल 286(3) है अभी सेल टैक्स पर कोई पाबदी नही है। हम अनाज के ऊपर टैक्स बढ़ाना चाहते थे ताकि भाकडा डैम का कर्ज अदा कर सकें लेकिन हमको सलाह दी जाती है केन्द्रीय वित्त मत्रालय से कि तुम सेल्स टैक्स नही बढ़ा सकते हो। यह बताया जाता है कि आर्टिकल 286(3) के अन्दर केन्द्रीय सरकार के पास शक्ति है कि वह कोई नया कानून बना कर प्रदेश की सरकारो पर पाबंदी लगा सकती है। लेकिन अभी उस आर्टिकल के अन्दर पाबंदी नही लग सकते। तो मै कहूंगा इसके साथ यह भी समझना जरुरी है---जैसा कि अभी बताया---राज कमेटी है, विशेषज्ञ है उन्होंने सिफारिशें की हैं। हर साल 3,000 करोड़ रु० निर्यात कर है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैं---या निर्यात कर या आयात कर। जो भाई माग करते हैं देश के किसानो के उपर टैक्स बहुत कम लगा हुआ है उनके सोचने वाली बात है। उनको यह सोचना पड़ेगा कि निर्यात

[श्री रणबीर सिंह

कर चाहे वह काफी का हो, चाहे टी का हो, चाहे पटसन का हो इसका निर्यात कर जितना कम किया जाएगा उतना ही किसान के पास ज्यादा पैसा होगा। दूसरी मानी में वह किसान का पैसा है, किसान का अपरोक्ष टैक्स इन्डाइरेक्ट टैक्स है। तो यह भी समझना चाहिए (*Time-bell rings*) वित्त मन्त्रालय को कि यह जो कहनी है कि किसान के ऊपर टैक्स कम है यह सही नही है। जो हमारी कर नीति है उसके नतीजे के तौर पर हिन्दुस्तान के किसान के ऊपर जो टैक्स लगता है वह कम नही है।

श्री जगदीर सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने तीन बिल्स है जिन्हे मन्त्री महोदय ने पेश किया।

"The Union Duties of Excise (Distribution) Amendment, Bill, 1974; The Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Amendment Bill, 1974 and The Estate Duty (Distribution) Amendment Bill, 1974."

इन तीनो बिलो को पेश करते हुए हमारे मन्त्री जी ने कहा था छठी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद उन्होंने इन बिलो के द्वारा धन का बंटवारा किया है। इससे यह मालूम होता है कि कितना धन स्टेट में रहेगा और कितना धन सेन्टर में रहेगा। साथ ही साथ मन्त्री महोदय ने यह भी बतलाया था कि वह तमाम सिफारिशें जो फाइनेंस कमीशन ने की है उन्हे सरकार पूरा करने मे असमर्थ रही है। मुझे इस बात का ज्ञान नही है कि सरकार उन्हे पूरा करना चाहती है या नही।

उपाध्यक्ष महोदय जहां तक इन बिलो को देखने से अन्दाजा होता है उससे एक बात साफ जाहिर है कि इस बार पापुलेशन बेस पर धन का बंटवारा किया है और साथ ही साथ कुछ पैसा बढा भी दिया है पहिले के मुकाबले में जो स्टेटों को दिया जाता था। यह एक अच्छी चीज है जो देखने को मिलती है। लेकिन आज प्रश्न यह है कि जो धन राज्यों को दिया जाता है उस पैसे का उपयोग किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से होना चाहिये हमारी समस्या तो यह है कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर है या नही? अभी श्री नवल किशोर जी ने कहा था कि इन बिल्स का लिमिटेड स्कोप है लेकिन मै यह कहना चाहता हू कि इसकी वाइड शक्ति है। आज तमाम देश की समस्या जो है वह इन पैसो के जरिये से सुधारी जा सकती है और या फिर जो आप टैक्स लगाते है उनके जरिये से जो पैसा मिलता है उसके द्वारा हम कुछ कर सकते है। लेकिन मेरे विचार मे आज फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बीच मे कोआर्डिनेशन नही है। आज फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बीच मे कोई तालमेल नही है। प्लानिंग कमीशन जिस किस्म की प्लानिंग करता है उनके लिए पैसे देने की जिम्मेदारी फाइनेंस कमीशन की है या नही? क्या फाइनेंस कमीशन इस बारे मे स्वय बतलायेगा या फिर प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन से पूछेगा कि वह कितना पैसा दे सकता है। इस वक्त किस किस्म की प्लानिंग हो रही है यह बात किस को मालूम नही है?

उप-सभाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज यह बात किसी से छिपी नही है कि हमारे देश की हालत रोजाना खराब होती चली जा रही है। आज बेरोजगारी हमारे देश में चरमसीमा पर पहुंच गई है। कीमते इतनी बढ चुकी है कि एक आर्डिनरी आदमी के लिए बरदाश्त करना असम्भव है। इतना ही नही आज हर आदमी को खाने के लिये अपना जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो गया है। आज हमारे देश मे 70 प्रतिशत बच्चे माल-न्यूट्रेशन की वजह से अन्धे हो जाते है और लाखों इस कमी की वजह से मर जाते है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका सीधा सीधा कारण यह है कि हमारी जो पालिसियां है वे डिफेक्टिव हैं हमारी पालिसियों के अन्दर कमी है। दरअसल आज जिन लोगों के हाथ में बागडोर है उनका हिन्दुस्तान के देहातों से कोई संबंध नही है जब कि देहातो के अन्दर हिन्दुस्तान रहता है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था "India lives in the villages and

not in the cities" उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके द्वारा सरकार से जानना चहता हूं कि क्या यह सही नही है कि हमारे देश के अन्दर जितनी भी नीतियां और प्लान बनाये जा रहे है उसके द्वारा शहर और गाव के बीच डिसक्रिमिनेशन किया जा रहा है। क्या गाव वालो ने इन पाच प्लानो के अन्दर उतना ही नफा उठाया है जितना शहर वालो ने उठाया है ? मेरा निश्चित मत है, नही। शहर में रहने वाले लोगो ने ज्यादा नफा उठाया है बनिस्बत गाव मे रहने वालो के जो झोपड़ी मे रहते है। उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से जानना चाहता हू कि क्या यह सही नही है कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत कम पैसा खर्च किया गया जो हमारी बैकबोन है। अगर आप फिफ्थ प्लान को देखे तो इसमें 13 प्रतिशत पैसा खर्च होगा एग्रीकल्चर के ऊपर, 7 प्रतिशत खर्च होगा इरिगेशन के ऊपर और 24 प्रतिशत खर्च होगा इडस्ट्रीज के ऊपर। कारण क्या है ? जैसा मैने कहा हमारे सोचने के तरीके मे अन्तर है सोचने का तरीका डिफेक्टिव है, हमारी पोलिसीज के अन्दर डिफेक्ट है। हमारे देश के अन्दर जो प्लानर्स है उनका विचार है कि इस देश की गरीबी, इस देश की मंहगाई और बेरोजगारी को देश का इडस्ट्रियलाइजेशन करके समाप्त कर सकते है। मेरा विचार यह नही है। मै समझता हूं कि हम हैवी इडस्ट्रीज को लेकर इस देश की गरीबी को सैकड़ों वर्षों तक नही मिटा पाएंगे। इस देश की गरीबी को मिटाने की कुंजी एक ही हो सकती है और वह यह है कि हम कृषि को बढ़ावा दे, कृषि की पैदावार बढ़ायें और अपनी पोलिसी ऐसी बनाये जिससे खेती की पैदावार बढे।

साथ ही साथ स्माल-स्केल इडस्ट्रीज हमारा उद्देश्य होना चाहिए। स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज को हमें बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन हालत क्या है। मै हैवी इडस्ट्रीज के विरोध में नही हू। मैं यह नही कहता कि हैवी इडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि जिन चीजों को हम छोटे पैमाने पर पैदा कर सकते हैं उन चीजो में हैवी इंडस्ट्रीज नही होनी चाहिए। मुझे तकलीफ नही होगी अगर आज गांव-गांव में करघे चलने लगे और हम सूती कपड़ा मिलों को बन्द कर दें। मुझे तकलीफ नही होगी अगर आज शुगर मिलो को बन्द कर दे और छोटे पैमाने पर शुगर का बनाना शुरू कर दें। उससे अनएम्प्लायमेंट खत्म होगा, देश की गरीबी भी दूर होगी और हमारी पोलिसीज मे परिवर्तन आएगा। मै समझता हू कि जो गाव के रहने वाले है उनक भी इससे बहुत कुछ सुधार होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत पुराना मत रहा है और आज भी है कि हमारी जितनी गवर्नमेंट रही है सेन्टर मे या प्रदेशों मे, उन्होने अन्तर किया है गांव के रहने वालों मे और शहर के रहने वालो के बीच। आज आकड़े बतलाते है कि गाव मे रहने वाले के मुकाबले शहर के अन्दर रहने वाले की आय साढ़े तीन गुना है। लेकिन आय साढ़े तीन गुना होते हुए भी जितनी पोलिसीज होगी, जितनी नीतियां होगी उनमें शहर वाले को प्राथमिकता दी जायेगी बनिस्बत गांव में रहने वाले के। मिसाल के तौर पर मैं बिजली की बात लेता हूं। क्या यह आवश्यक है कि इस देश के अन्दर दिल्ली में और लखनऊ मे रोज बिजली मिले और गांव वालो को सिचाई के लिए और थ्रैशिंग के लिए भी बिजली न दी जाय तीन-तीन दिन तक मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, विद आल दी इम्फोरमेशन एट माइ डिस्पोजल कि आज हमारे प्रदेश के अन्दर गांवो में तीन-तीन, चार-चार दिन तक बिजली नही दी जाती ट्यूब वेल्स को और थ्रशिंग के लिए। क्या करेगा किसान ? कहा इन्सेन्टिव है किसान को अधिक पैदा करने के लिये ? जब इन्सेन्टिव नही होगा तब आप क्या अधिक पैदावार लेगें ? आपके आंकड़े कहते हैं कि इस वर्ष 103 मिलियन टन अन्न पैदा होगा। 10 वर्ष पहले भी आपका यही आंकड़ा था और वही आज भी है कोई बढोत्तरी नही है। आपकी पैदावार वही होगी जो 10 वर्ष पहले थी जबकि आज यू हैव मोर माउथस टु फीड। यह देश की हालत हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हू कि सरकार इन समस्याओ की ओर ध्यान दे तथा गांव के प्रति और किसान के प्रति जो उसकी सौतेली-मां-की-नीति है, उसको छोड़े।

इस बात की बड़ी चर्चा है कि किसान बड़ा अमीर हो गया है किसान की उपज के भाव बहुत हो गए, उसका गेंहूं बहुत दाम पर बाजार में बिकता है। मै जानना चाहता

[श्री रणबीर सिंह]

हूं अपने इन दोस्तों से कि हमारे पास कितना सरप्लस है, कितना सरप्लस देगा हरियाणा, कितना सरप्लस देगा वैस्ट यू० पी० ? हमारे पास खाने के लिए न हो तो आप भाव 300 रुपए से ऊपर भी कर देंगे तो हम नहीं देंगे । हम कहते हैं कि आपने हमें पानी दिया होता, आपने हमें फर्टिलाइजर दिया होता ठीक कीमत पर, आपने बिजली का इन्तजाम किया होता तो गल्ला मन्दा ले लिया होता, लेकिन अब तो पैदावार ही नहीं है । फिर भी आपके दिमाग में यह है कि किसान बड़े मालदार हो गये हैं, किसान के ऊपर टैक्स होना चाहिए, किसान के ऊपर टैक्स कम हैं । मैं कई बातें कहना चाहता हूं कि आज किसान की जो हालत है वह कई तरीके से नापी जा सकती है । आज हम देखते हैं कि किसान जब बाजार में जाता है तो वह अपनी चीजों को बेच दिया करता है होलसेल में और जब चीजें खरीदता है तो वह रिटेल में खरीदता है । आपने कभी देखा नहीं होगा कि वह होलसेल में कपड़ा खरीद लाया हो । अगर आप कंपैरिजन करें किसान की आवश्यक वस्तुओं की रिटेल प्राइस का और जो उस का सरप्लस है उसकी होलसेल प्राइस का तो आपको मालूम होगा कि किसान की जरूरियात की रिटेल प्राइस ज्यादा बड़ी है बनिस्बत किसान की होलसेल प्राइस के जो वह बाजार में बेचता है । जब तक हमारे दिमाग से यह बात नहीं निकलेगी कि गांव में रहने वाला मालदार हो गया है तब तक इस देश की प्रगति नहीं होगी ।

इतना ही नहीं, एक नीति नहीं, हजारों नीतियां आप देख लीजिए । मैंने बिजली की बात कही । मैं साफ साफ उन गरीब मजदूरों की बात कहता हूं जिनके लिये हमारे दोस्त कहते हैं अगर उनका कोई हितैषी है तो केवल कांग्रेस है अथवा कोई नहीं यह दावा है इनका । लेकिन करते क्या है उनके लिए आप सुन लीजिए । एक तरफ इनकी नीति है कि राशन की दुकानें खोलें । वह राशन की दुकानें हमारे देश में खोली गई हैं तो किसके लिए ? जिनकी आमदनी 300-400 रुपये या उससे अधिक है, जो शहर में रहते हैं उन लोगों के लिए । गावों में रहने वालों मजदूरों के लिए जिसकी आय सौ रुपये और 50 रुपये से कम हो उनके लिए नहीं । क्या यही है इनका समाजवाद ? किधर ले जायेंगे देश को ? गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाते चले जायेंगे । हमारी सरकार जो बैठी हुई है कुर्सी पर यह है इसका समाजवाद ।

मैं इन शब्दों के साथ एक बार फिर मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि वह अपनी पालिसीज पर ध्यान दें, प्लानर्स से यह बात कहें कि इस प्रदेश का भला तभी हो सकता है जब ऐसी पालिसी हो जिससे खेत की पैदावार बढ़े, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बढ़े जब ये चीजें बढ़ेंगी तब हम देश की पैदावार बढ़ा सकेंगे । तभी हमारे देश की तरक्की हो सकेगी और भविष्य उज्ज्वल ।

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ (Himachal Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I welcome all the three Bills that are under discussion because to me it looks that they are a step towards meeting the long outstanding demands of the people in the backward States. The difficulty with backward States is not only their backwardness and poverty but other things also which are there. For example, I may give the illustration of my State, Himachal Pradesh. You know that in addition to the problem of its backwardness, there are problems which nature has created for it. If you have to construct a road in Himachal Pradesh, it will cost ten to twelve times more than it costs in the plains. Now, if people living in different corners of the country are to be given some relief in this age of socialism and democracy, it is very essential that more and more expenditure has to be incurred for their sake. Similar is the problem in Jammu & Kashmir and similar is the problem in Nagaland. So, I would say that Government has been good enough to move these Bills and at least concede that in the matter of distribution of auxiliary taxes. The basis will not only be population but the backwardness of the State also. In this connection, I would suggest that besides the backwardness of the State concerned another factor which should be taken into consideration is the natural position of the State. For example some gentlemen were saying that there are small States and they have so many problems. These are not at all problems. These States are working

3 P.M. as defenders of the country; they are at the borders. They are keeping life alive over there; otherwise all these areas will become no man's land and who will protect the country in that event ? Therefore it is highly essential that this difficulty of these States at the borders, particularly the hilly States, may be kept in view and not only 25 per cent be distributed on the basis of backwardness but another 25 per cent may be distributed on the basis of natural circumstances, the position of the State and hilly areas. I am not against other States but there is this additional difficulty here. In the States in the plains also there are difficulties but here in the hilly areas the difficulties are more. For example, Himachal Pradesh has more area than Haryana but its population is 35 lakhs whereas the population of Haryana is about a crore. So I am not against Haryana or any other State ; I am merely putting my case just for the sake of illustration. Because of these reasons it is very essential that the density of the population, that is, the percentage of density of population should be given great consideration in the matter of distribution of funds for backwardness. My second demand is that the position of the State should be another criterion for the distribution of the proceeds of these taxes, if not of all the taxes. I would urge upon the Government to keep this demand in view that another 25 per cent should be distributed on the basis of the State's natural position and the remaining 50 per cent may be as usual distributed on the basis of population.

I have not taken much time so I would like to refer to one more thing. There was a controversy about rural areas and cities. I think it is not a very good thing to have such controversies because there was a time when all of us, almost all of us, were people of the villages. When we become leaders and when we come to occupy high positions in the party then our first concern becomes to have a house in the city. When we shift to the cities like that, then why do we talk about the villages ? (*Interruptions*). When people become leaders their first concern is to shift to the city and have some arrangement for building houses there.

SHRI JAGBIR SINGH : They cease to be leaders then.

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : They forget the villages though they talk about the villages on the floor of the House.

SHRI RANBIR SINGH : They may be living in the cities but they are the advocates of the villages.

SHRI JAGAN NATH BHARDWAJ : They will only go on talking about villages. Why do they talk about them when they themselves have forgotten them ? This question can never be satisfactorily solved and will never be satisfactorily solved.

With these words I support the Bills.

SHRI VISWANATHA MENON (Kerala) : Sir, the hon. Minister, while introducing these Bills, stated that the recommendations were based on the recommendations of the Sixth Finance Commission and they have all been accepted by the Government. The Bills are based on the recommendations. My first comment is the recommendations and the Bills are disappointing. Before going into the allocations to various States I want to deal with the allocation made to the States pool. Now, all the States in India are in a difficult position. When taxes and excise duties and other revenues are being collected by the Centre and the distribution is done in such a meagre way, naturally the position of the States would be more difficult. The Centre-States relationship has become a big problem all over India. We claim that our Constitution is based on federal principles, but practically a unitary form of government is functioning here and for every small thing the States have to depend on the Centre. In this connection I want to draw your attention to the fact that a week before even the cheques issued by States like Kerala, Karnataka and Andhra were dishonoured and our Finance Ministers had

[Shri Viswanatha Menon]

to rush to Delhi for help. This position must be changed.

We expected many things from the Sixth Finance Commission. My State Government, *i.e.*, Kerala, and various political parties have demanded more contribution to the States' Pool. At least 75 per cent of the taxes and duties must be given to the States' pool. Then that must be distributed to the weaker sections among the States. As in the case of the Fifth Finance Commission or the Fourth Finance Commission, the same thing has happened, ignoring the needs of the State. The Commission has come out with such data which are really making us disappointed. In this connection I want to draw your attention and through you the Minister's attention to the position of Kerala. I want to read a particular portion from my States Government's publication. It says :

"Kerala with a geographical area of 38,855 sq. km. *i.e.*, 1.3 per cent of the total area of the country has a population of 21.35 million which is about 4 per cent of the country's population. The population density in the State is thus very high, being 548 which is more than three times the all India average. The percentage of rural population is 83.72 in the State as compared with the all India average of 80.12.

Out of the State's total geographical area, nearlly 27 per cent is under forest. About 56 per cent would represent the area available for cultivation. The per capita availability of cultivable area in the States is only 0.11 hectare as compared with the all India average of 0.29 hectare. While about 70 per cent of the total cropped area in the country is under foodgrains, the corresponding figure for Kerala is only 30 per cent and the major food crop of the State is paddy. Since the area under foodgrains is small, the State is compelled to import more than 45 per cent of its food requirements. More than 50 per cent of the total cultivable area is devoted to the cultivation of commercial crops such as coconut, arecanut, rubber, tea, coffee, cardamom, pepper etc. The State contributes about Rs. 150 crores annually towards the country's foreign exchange earnings.

The per capita income of the State is less than the all India average. In 1968-69, the State's per capita income (at current prices) stood at Rs. 526 as against the corresponding national average of Rs. 555.

The major component of State's income, 58 per cent, is accounted for by the agricultural sector, and it is 7 per cent higher than the corresponding national average of 51 per cent."

Sir, I am quoting this to state the facts and to consider the backwardness of my State. In these allocations, in all spheres, it is all below 4 per cent. Without developing our State industrially, what is the use of criticising that we are going everywhere for job. Wherever you go in India or to even Dubai or Kuwait or Paris or Italy, you will see the Malayalees working there.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : You are a major export.

SHRI VISWANATHA MENON : Why are we working there ? It is not because we are enamoured of going there but because we are not getting any job in our place. The major problem of the State is unemployment. How to solve it ? The only way to solve it is by industrialising that State. To the Central Government we are giving a lot of foreign exchange, to the tune of Rs. 150 crores, to the Central pool. But the Central Government is acting in a step-motherly way towards Kerala. And the position of Kerala is going down day by day. If we go to Bombay for job, the Shiv Sena will come and beat us. If we go to Bihar, we get reports that there also we are beaten. If we go to Tamil Nadu, even there we are beaten. What can we do ? Sir, the basic point is that the Central Government is to visualise even now about the so-called national integration.

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Nadu) : The word 'beaten' may not be used.

SHRI VISWANATHA MENON : We were beaten at Arkonam ; I have got reports like that.

If you cannot stop it, if it is being continued, what is the use of talking about national integration and all that ? . Are we responsible for that ? If the Government of India and the hon. Minister ask us to cut down all the commercial crops that are earning foreign exchange to this country and to go in for paddy cultivation then we will get food. Is it wise to do that ? Without considering the problems of Kerala, without considering our burning problem of unemployment the culculated neglect is continuing towards Kerala. We have been given some hopes. We were expecting some consideration. But it was not shown to us.

Moreover, I want to state before this honourable House that unfortunately, the people of Kerala are educated. The entire Kerala people are literate. I use the word 'Unfortunately' because despite education, we are not getting any job. Thousands of engineering graduates, thousands of boys knowing technical subject, those who have got diplomas and certificates and degrees are walking through the streets of Kerala. If the hon. Minister, on behalf of the Government assure us that some industries will be given to us at least our boys will get some jobs. Sir, we have got the Sabarigiri project the Idikki Dam project will be over within a short time. We will have ample electricity. On the one side, we have got ample electricity; on the other, we have got ample technical know-how. Please give us some industries so that we can stand on our own legs, for the sake of self-sufficiency. Then we will not go anywhere, we will not go all over India begging for our food. We have built Bombay along with the Maharashtrians or the Gujaratis or those who are staying there. We have done it with our blood, we have poured our blood and sweat to develop Bombay. Now, we have been asked to get out of Bombay "jobs for the sons of the soil" is the slogan. The same slogan is being raised all over India, in various places, and in various forms. What can we do? The responsibility is with the Centre to start doing something to develop Kerala. If Kerala is developed we will not go any where. The unemployment problem has become such a big problem. The Central Government has got full knowledge of all these facts. With the full knowledge of facts when these Bills have come before us and our hon'ble Minister is asking us to vote for them. I do not know what to do. We are told that we must be satisfied with 4 per cent. The attitude of the Central towards the States must be changed—let me stress in this august House, that you cannot expect the States to become colonies of the Delhi Badshahi. Let me say that we are not prepared to be slaves of the Delhi central administration. We must get our share. The States must be given at least 75 per cent. of the total earnings of their revenue that is being collected through taxes and excise duties and other things. You ask us to accept 4 per cent, 2 per cent. or 1 per cent. This sort of distribution will not do any good for the nation.

Sir, we all claim that we are one nation. We all talk of national integration. But when the question of treatment comes, when the question of Kerala comes, we are told that we are the Southernmost people and we should not come to other States. We are asked to go away. Sir, if it is one nation, then every portion of this country must be developed, and for the development of this country the main point is industrialisation. Regional imbalances in industrialising this country must be curbed. Without doing all these things, simply the slogan of 'Garibi Hatao' will not help. The problems of the States and Centre relationship cannot be solved unless regional imbalances are removed.

Lastly, I would request the hon'ble Minister, through you, Sir, to say on the floor of the House, if she can, that 75 per cent. of the excise duties and taxes will be given

[Shri Viswanatha Menon]

to the States and the Kerala people will be given the portion to which they are legally entitled.

श्री कल्पनाथ (उत्तर प्रदेश) . उप-सभाध्यक्ष महोदय, श्रीमान मै इस बिल पर बोलने से पहिले यह निवेदन करना चाहता हू कि आजादी के 25 वर्ष बाद भी हमारे उत्तर प्रदेश का और विशेषकर हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तो का ठीक ढंग से विकास नही हुआ है जिस के कारण हमारा ग्रामीण उत्तर प्रदेश और बिहार का हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश बिल्कुल पूर्ण रूप से पिछड़ गया है । मै सरकार से यह कहना चाहता हू कि आज हमारे देश मे प्लानो को चालू करने के लिए जितने फाइनेंस कारपोरेशन्स है, चाहे वह रिजर्व बैंक आफ इंडिया हो, चाहे यूनिट ट्रस्ट आफ इडिया, चाहे वह इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कारपोरेशन हो इडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन हो, इस तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशन्स है उनके दफ्तर बम्बई मे है । जब पूर्वी उत्तर प्रदेश की या बिहार की तरक्की की कोई बात होगी तो हमे पैसे के लिये बम्बई जाना पड़ेगा । हिन्दुस्तान के जितने भी फाइनेंसियल इस्टीट्यूशन्स है, उनके हैडक्वाटर्स भी बम्बई में ही है । एक यह भी सब से बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारे प्रान्त की तरक्की नहीं हो पा रही है। सब से बड़ा कारण तो पिछड़ेपन का यह है और दूसरा बडा कारण यह है कि हमारे यहां इन 25 वर्षों से डायरैक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाये जा रहे हैं । हमारे देश में योजना भी बनाई गई है लेकिन उसका परिणाम यह हुआ है कि हिन्दुस्तान में पहिले जहा 75 मानोपलिस्टिक हाऊसेज थे वहा अब उनकी सख्या 93 हो गई है । एक तरह से आज हिन्दुस्तान का जो गरीब आदमी है, उसकी गरीबी ज्यादा बढती ही चली गई है और दूसरी ओर जो देश मे पहिले 75 मोनोपलिस्टिक हाउसेज थे उनकी तादाद बढ़कर अब 93 हो गई है ।

हमारे देश में दो तरह के टैक्स लगाये जाते है । एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है । मै यह निवेदन करना चाहता हू कि इस समय जो टैक्स लगाये जा रहे है उनमे से कितने आवश्यक हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिये । सरकार जो लगातार जनता के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाती जा रही है उसकी वजह से उसकी पर कैपिटा इन्कम घटती ही चली जा रही है । इसके परिणामस्वरूप आज हमारा देश दुनिया के देशो में 100 वे नम्बर मे चला गया है । डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए हम रुपया देते है, लेकिन ज्यादातर पैसा खर्च होता है नान-डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर । अगर 5 करोड रुपया सिचाई के लिये डैम बनाने के लिये दिया जाता है तो ढाई करोड़ रुपया उसमे एस्टेबिलशमेंट के ऊपर खर्च होगा, 1 करोड़ रुपया कन्ट्रेक्टर्स के पाकेट मे होगा, 1 करोड रुपया उस काम पर खर्च होगा । हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक कमीशन बनना चाहिए यह तय करने के लिये कि डैवलमेंटल कार्यो में जो नान-डैवलपमेंट खर्चे 75 परसेंट हो जाते है उनके बारे मे मुनासिब नीति क्या होनी चाहिये ।

दुनिया के बाहरी देशो से जो हम बेसिक इंडस्ट्रीज को डैवलप करने के लिये चीजे इम्पोर्ट करते है, उन पर टैक्स कम लगाना चाहिए । जो मिडिल सैक्टर की इंडस्ट्रीज के लिए चीजें इम्पोर्ट करते है उन पर भी टैक्स कम लगाना चाहिए । जो चीजे विलासिता के लिये इम्पोर्ट होती है या कन्जम्शन-ओरिएन्टेड इकोनोमी के लिए जैसे लिपिस्टिक के या कोका कोला के बड़े-बड़े कारखाने एयर-कन्डीशनर्स, फ्रिज या इस तरह की दूसरी जितनी भी चीजे है शराब है, टुबेको है, उनके ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगानी चाहिये । जिन चीजो से गरीब लोगो का रिश्ता नही है उन पर ज्यादा ड्यूटी लगे लेकिन उल्टा होता है । परिणामस्वरूप हम प्रोडक्शन-ओरिएन्टेड इकोनोमी नहीं कर पाए है और यही कारण है कि हमारा उत्तर प्रदेश पिछड़ गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पापुलेशन के हिसाब से फंड्स का एलोकेशन होना चाहिए । उत्तर प्रदेश की आबादी है 9 करोड़, बिहार की आबादी है 5 करोड़ लेकिन पापुलेशन के हिसाब से पैसे का एलोकेशन कभी नही किया गया । हमने हमेशा अग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की । परिणाम यह हुआ कि तब भी नैगलैक्टेड रहे और जब देश की हुकूमत बनी उस समय भी उत्तर प्रदेश और बिहार हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त पीछे रह गए क्योकि पर-कैपिटा

[श्री कल्पनाथ]

के हिसाब से, पापुलेशन के हिसाब से फण्ड का एलोकेशन नहीं हुआ। जब सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एलोकेशन होता है तो हमें बैकवर्ड एरियाज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, यह देखना चाहिए की हिन्दुस्तान के नक्शे में कितने प्रान्त है जो बैकवर्ड है, कितने प्रान्त है, जो डेवलप्ड है। हम चौपाटी को, कलकत्ते की चौरंघी को राष्ट्रपति भवन को देखकर हिन्दुस्तान की तरक्की का अनुमान नहीं लगा सकते। मैं समझता हूं कि 25 वर्ष के आयोजन का यह परिणाम रहा है कि हमने गरीबी के रेगिस्तान में कुछ विलासिता के नखलिस्तानो का निर्माण किया है, हमने गरीबी के महासागर में कुछ टापुओं का निर्माण किया है, जिनको देखकर हम हिन्दुस्तान की तरक्की का दम भरते है।

श्रीमन्, सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान उस उपेक्षित पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ ले जाना चाहूंगा जहा की डेनसिटी आफ पापुलेशन चीन के बराबर है, वहा लाखों पढे-लिखे बेकार है तथा जहां करोड़ो बेपढ़े-लिखे लोग बेकार है। जब ये लोग बम्बई या कलकत्ता मे चपरासी या कुली की नौकारी खोजने जाते है तो वहां भी इनकी झुग्गी-झोपड़िया शिव सेना द्वारा जला दी जाती है।

पूर्वांचल उत्तर प्रदेश एव बिहार आजादी की लड़ाई में सबसे आगे, परन्तु आजाद भारत में आर्थिक, औद्योगिक दृष्टि से सबसे पीछे क्यों उपेक्षित पूर्वांचल उत्तर प्रदेश एव पिछड़े बिहार के आकड़े अन्धे, बहरे एव गूंगे को भी इस भूभाग के नागरिको की महानुभूति मे दौड़ने और बोलने को मजबूर कर देने है। मगर राजनीतिक प्राणी को भी क्या? क्योंकि वही तो उत्तरदायी है मुख्यत: इनके पिछडेपन के लिए। कभी ये राजनीतिक विदेशी थे, आज देशी है। शासन करने वाले किससे घबराते है--जो बेअदब विद्रोही हो, हर बात पर सलाम न करे, शांतिपूर्ण एव आज्ञाकारी रियाया बन मालिक का हुक्म न बजाए। हिन्दी प्रान्तवासी इसी अपराध के सबसे बडे दोषी है। इसीलिए तो सजा मिलनी लाजमी है। इसका इतिहास साक्षी है कि खैबर और बोलन दर्रे से आने वाले आक्रामको को पहला मोर्चा बराबर उत्तर प्रदेश के सदर पश्चिमी भू-भाग में लेना पड़ा। पानीपत की मिट्टी मे पूछिए जो तीन बार खून की धार में नहा चुकी है। पंजाब की उर्वरा भूमि को बराबर शान्तिपूर्वक उपजने, महकने और चमकने का अवसर मिलता आया है।

सन् 1858 की आजादी की पहली लड़ाई पाटलिपुत्र से पानीपत तक मार्शल रेस तब य थे, अब और है। ये लड़ाकू थे, वे लडाका है। कारण स्पष्ट है, विद्रोह करने वालो के बेटे माली और चपरासी, कुली बने, सूखी जमीन के भूखे किसान रहे। सन् 1942 के स्वतत्रता संग्राम की लड़ाई भारत भूमि के चप्पे-चप्पे पर लड़ी गई। मगर इस बात से कौन इकार कर सकता है कि इन्ही उपेक्षित हिन्दी प्रदेश के बड़े भू-भाग पर अंग्रेजी शासन का नामोनिशान जिस प्रकार मिटा दिया गया, वह इतिहास की धरोहर है। ऐसे विद्रोहियों को भला अडमान नहीं भेजा जाये तो क्या फौज मे भरती किया जाये? इन्हें नहर क्यो? बजर जमीन मिलनी चाहिए। बिजली क्यों, लालटेन की टिमटिमाती रोशनी रहनी चाहिये। दोनों वक्त क्यों एक वक्त भी कुछ खाने को मिल जाये यही क्या कम है। यह है ऐतिहासिक कारण इसके पिछड़े-पन का।

आजादी के बाद अपनी सरकार बनाने के लिये अपना राज-गौरव मिला उत्तर प्रदेश को कि वह भारत को तीन प्रधान मत्री दे और बिहार को तो प्रथम राष्ट्रपति प्रदान करने का शुभ अवसर मिला। परन्तु चिराग तले पिछड़ेपन का अन्धेरा कायम रहा। स्वाधीनता सग्राम के बड़े-बडे पुरुष और जननायक इस भू-भाग मे अवतरित हुए जिन्होंने 1921 से लेकर 1947 तक अपूर्व त्याग और बलिदान का परिचय दिया। आजादी प्राप्त की शासक बने परन्तु ब्रिटिश साम्राज्यवाद की पोशाक नौकरशाही आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस० ने नई लोकशाही पर आधारित सामाजिक आर्थिक नई व्यवस्था का अनवरत विरोध किया। फलत: स्थिर शासन के नाम पर इन्होंने एक वर्ग विशेष के [illegible] को बढावा दिया, इसे उभारा

[श्री कल्पनाथ]

और उसे जनसाधारण की प्रगति की सज्ञा दी। प्रशासनिक स्तर पर राजनीतिज्ञो एव नौकरशाही की यह दाल कटी रोटी पिछड़ेपन का कारण बनी रही।

सास्कृतिक एव बौद्धिक स्तर पर हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों के शासनकर्ता कुछ खादी में लिपटे हुए कुछ 'क्लब आफ दि लाइट' में पाश्चात्य नृत्य और सगीत की धुन पर नये-नये परीक्षण अपनाते, आजमाते, आग्ल भाषा की डोर में बधे अखिल भारतीयता का झूठा नकाब पहने भारत के अन्य भागो की अपनी बिरादरी भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ मिलकर देश पर छाए रहे।

बिहार सपूर्ण भारत के खनिज पदार्थो की किस्म और परिमाण का सबसे बडा आगार है। पूजी भी बहुत लगी है। मगर यहा के निवासियो की मासिक, वार्षिक औसत आमदनी सबसे कम है। रोजगार मे स्थानीय लोग बहुत कम है। बिहार की आबादी दस प्रतिशत है किन्तु भारतीय प्रशासनिक सेवा मे दो प्रतिशत। मद्रास की आबादी दो प्रतिशत है परन्तु प्रशासनिक सेवा मे पच्चीस प्रतिशत। सभी बड़े-बड़े उद्योगो एवं कल-कारखानो के मुख्यालय कलकत्ता मे है। उत्पादन बिहार में होता है और लाभाश कलकत्ता और बम्बई को। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में जहां हिन्दुस्तान की सबसे ज्यादा चीनी मिले है, गाजीपुर के अफीम कारखाने में सर्वाधिक फारेन एक्सचेज मिलता है, गौतम बुद्ध का गोरखपुर, देवरिया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का फ़ैजाबाद, भारत की सास्कृतिक राजधानी काशी, बनारस पूर्वांचल उत्तर प्रदेश है जो हिन्दुस्तान मे सबसे पिछड़े हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० वी० राज्) आप उत्तर प्रदेश और बिहार दोनो को मिलाकर बोल रहे है। . .

श्री कल्प नाथ जहाँ सर्वाधिक फारन एक्सचेज मिलता है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके सबसे पिछड़े हैं। जहा लाखो पढ़े लिखे बेकार है तथा लाखों बेपढ़े पिछड़े आदिवासी हरिजन-गिरिजन बम्बई और कलकत्ता की गलियो मे ठोकरे खाने के लिए मजबूर है, उस पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए आजाद हिन्दुस्तान की सरकार ने योजना आयोग की रिपोर्ट पर पटेल कमीशन बैठाया, मेहता कमीशन बैठाया, परन्तु वहा के पिछड़ेपन के लिए वहां के बेकारो को काम देने के लिए, खेतों को पानी देने के लिए उस इलाके के औद्योगीकरण के लिए कोई ठोस एव समयबद्ध कार्यक्रम नही लागू किया गया।

दुनिया मे सबसे ज्यादा बढिया हैंडलूम के कपड़े मऊनाथभजन मे बनता है। वहा की साड़िया, मिर्जापुर के कालीन सारी दुनिया मे महशूर है पर ये इलाके सबसे पिछडे हुए है। सबसे निर्धन है। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने कोई भी इनको आर्थिक मदद इडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं दी है। डा० ज्ञानचन्द ने अपनी किताब 'टेमिंग मिलियन्स इन इडिया' मे लिखा है कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश की आबादी चीन की डेन्सिटी आफ पापुलेशन से मुकाबला करती है। गोरखपुर, फैजाबाद, बनारस डिविजन के पूर्वी जिलो मे आज स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि लाखों की सख्या में लोग भागकर कलकत्ता, बम्बई, और दिल्ली मे कुली, चपरासी की नौकरिया खोजते हुए, बम्बई के 'अंधेरी की झुग्गी झोपड़ियो में भी चैन से नही रह पाते। [*Intersuption*] कभी शिव सेना इनकी झुग्गिया जला देती है, कभी पुलिस वाले इनको पकड़-पकड़ कर परेशान करते है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान मे दो सौ चीनी मिले आज कल है जिन मे से सौ फैक्टरिया यू० पी० और बिहार मे है। पच्चीस लाख किसान परिवार हिन्दुस्तान में गन्ना सप्लाई करता है। हिन्दुस्तान के सभी मोनोपोलिस्ट पूंजीपतियों के हाथो मे गन्ना मिले है और इन्ही गन्ना मिलों के माध्यम से पूजीपतियो ने अरबो खरबो रुपये लूटे है। यदि चीनी मिलो का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये तो इन्ही चीनी मिलो की आमदनी से पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में मैकडो कारखाने खुल सकते है तथा लाखो बेकार पढे-लिखे लोगो को नौकरिया मिल सकती है। परन्तु समाजवाद का नाम जपने वाली सरकार ने आज तक चीनी मिलो का राष्ट्रीयकरण नही किया। महाराष्ट्र मे कोआपरेटिव सेक्टर मे चलने वाली चीनी मिलों की रिकवरी 13 प्रतिशत है वही यू० पी० और बिहार की फैक्टरियां मे 9 प्रतिशत होती है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, चीनी मिल मालिको के करोड़ो रुपये की कहानी इसी से प्रमाणित

होती है कि एक चीनी मिल का मालिक मोदी कई मिलों के कारखानो का मालिक बन बैठा है। मै दिल्ली की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के एव बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अविलम्ब एक आयोग की घोषणा करे एव आयोग की सिफारिशो को ठोस ढग से समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा करे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दुनिया मे सब से अधिक नदिया बिहार एव पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में है। सब मे उपजाऊ भूमि इन्ही इलाको मे है। सब से अधिक खनिज पदार्थ लोहा, कोयला आदि की खाने इसी प्रदेश मे है। परन्तु दुनिया का सब से पिछडा गरीब और भूखण्ड इलाका भी यही है ऐसा क्यो ? धरती के पेट मे छिपा हुआ जल एव नदियो के बहते हुए पानी का ठीक ढग से इस्तेमाल किया जाय तो जल से बिजली, बिजली से खाद और फर्टिलाइजर से उत्पादन एवं उत्पादन मे तरक्की और जल से सिचाई की चतुर्दिक तरक्की की जा सकती है (Time bell rings) मुझे एक मिनट मे वित्त मत्री जी से निवेदन करना है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी भी विलासता की चीजे हैं उन पर अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाय और इस के अलावा मोनोपोली हाउसेज पर भयकर ढग से टैक्स लगा कर या उन की सपूर्ण आमदनी सरकार ले ले और इस के लिए यदि आवश्यक हो तो उन का भी राष्ट्रीकरण कर लिया जाय ताकि देश जनता को सहूलियत हो और उस के लिये जो जीवन की उपयोगी वस्तुऐ है जैसे मोटा कपड़ा है या और दूसरे खाद्य पदार्थ है, इडैबिल आयल्स है,वह उन को उचित कीमत पर मिल सके और इस के अलावा इडैबिल आयल्स पर कम से कम इन्डाइरेक्ट टैक्स लगाया जाय जिस से हमारे करोडो इसानो का पेट भर सके। ऐसा होने से जब गरीब जनता का और करोड़ों इसानो का पेट भरेगा तो उन मे एफीशियेंसी आयेगी और जब उन में एफीशियेंसी बढ़ेगी तो उस से प्रोडक्शन बढ़ेगा और जब देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देश की तरक्की होगी, अधिक धन होगा और हमारे देश मे अधिक कल-कारखाने होगे और ऐसा होने पर ही देश मे खुशहाली आयेगी। इन शब्दो के साथ जयहिन्द।

श्री श्यामलाल यादव : जो बात राजनारायण जी कहते है वह तो इन्होंने कह दी।

श्री राजनारायण : कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सही बात बोल रहे हैं। अभी तक एक आदमी ऐसा मिला है कि जो हिम्मत के साथ बोले। पिछले 25 सालों का सारा नक्शा उन्होंने खींच दिया। ऐसे आदमी को बोलने के लिए आप मौका नहीं देते।

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA: Mr. Vice-Chairman, I have just been listening to the very interesting and forensic speech of the gentleman from the other side. Unfortunately he was so fast that I could not get the proper translation of it. That was the only difficulty. He has covered the entire vista of economy of the country and it was very informative.

So far as I am concerned, I would like to restrict myself to the present Bills . . .

SHRI SARDAR AMJAD ALI : On a point of order. My friend Shri Gowda says that the speaker from our side was so fast that he could not get the translation of his speech. But then he makes the observation that he has covered the total economy of the country. How is it ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : He could not fully understand it.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : Let me explain to my friend Sardar Amjad Ali. Whenever they were able to translate here and there, I could hear that and from that I could imagine the entire vista that was covered.

श्री राजनारायण : थोड़ा सुन कर यह नतीजा निकला है, पूरा सुने होते तो फिर कांग्रेस मे रहते ही क्यों ?

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : Sir, coming to the three Bills which are before us now and which are based on the recommendations of the Sixth Finance Commission, I am inclined to support them because certain injustices which had been done by the Fourth and Fifth Finance Commissions particularly to the Southern States like Karnataka, Kerala and others have, to a certain extent, been remedied in the present Finance Commission's recom-

[Shri U. K. Lakshmana Gowda.]

mendations. Therefore, I welcome those provisions. But, however, the share of the States has been still kept at 20 per cent and then that has to be shared among the States on the basis of population and backwardness at 75 per cent and 25 per cent. I share the view expressed by my friend Shri Viswanatha Menon and others that this should have been more, that is to say, there should have been a greater allocation to the States sector in view of the present difficulties which all the States are facing. Sir, it is very evident that the major protion of tax revenue and tax collection from the Excise Duties, Income-Tax and other taxes accrues to the Centre and the States are left with very limited spheres for augmenting their resources. Sir, it has been suggested that a greater effort at collection of agricultural taxes would ease the situation. Unfortunately, Sir, particularly with reference to the Southern States, here also there is a great limitation because there is already the tax effort in respect of the commercial crops which are predominantly grown in the Southern State of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu and there is a very heavy incidence of agricultural income-tax which is restricted to the commercial crops in Tamil Nadu and Karnataka, but which has been extended in Kerala to other agricultural products also. This is a great limitation and there is not much left for augmenting the resources and these States in view of the difficulties which they are facing, have to depend more and more on the Central assistance and it is in the fitness of things that in the future greater efforts should be made to find from the centre both Plan and non-Plan allocation in greater measure to the States.

Sir, as has already been pointed out here, the three Southern States which grow commercial crops are large foreign exchange earners and that, to a great extent, compensates the foreign exchange deficiencies of the country and substantially contributes to increasing our foreign exchange earnings. This fact must be always borne in mind. My friend, Sir, Shri Ranbir Singh, was mentioning about the production of wheat and other agricultural produce in Haryana and Punjab which have been feeding, to a great extent, the different parts of the country. We are thankful to them. But they also should not forget that by earning foreign exchange through the production of commercial crops in our States we are also helping the nation and we must be compensated for what we lose. Sir, it is not possible to remove the commercial crops where they are now grown and grow other food crops there because the terrain is such and even doing that, wherever possible, is not also desirable as the country needs commercial crops also. If you take into consideration the unit value of these foreign exchange earning commodities, Sir, you will find that they are the ones which have remained more or less steady in their prices. What you get in exchange, that is, what a unit value of a commercial crops from the Southern States would buy by way of consumer goods like foodgrains and other things has sharply dwindled now, because what we used to get for, say, the value of a hundred kgs. of rubber or tea or coffee by way of consumer goods, we are now getting very much less and this one point must be borne in mind and it must also be remembered that we are still contributing our share to the welfare of the entire nation.

Then, Sir, my friend, Shri Bipinpal Das, made a particular reference to the Excise Duty on tea. It is a fact, Sir, that the present system of levy of Excise Duties is very irrational and he quoted the example of Assam paying more than Nilgiris. Even if we accept that, it should be noted that even in the Southern states for the common tea that is produced there the Excise Duties are higher compared to their profitability. So, the whole thing has to be rationalised and I understand that there is already some discussion going on between the producers' organisations and the Finance Ministry and I hope immediate attention will be paid to this.

Then, Sir, I will come to the question of coffee. Unfortunately, Sir, I was not here when the Finance Bill was discussed the

other day and my friend, Dr. K. Mathew Kurian and Shri K. Chandrasekharan, have raised this issue. Sir, in the recent Budget, the Excise Duty on the lower grade of coffee, that is, the Robusta variety, which is the major internal consumption part of the coffee produced in this country, has been increased from Rs. 60 per quintal to Rs. 100 per quintal.

Originally, on Arabica coffee, which is a superior grade of coffee, most of which is exported, excise duty was levied at Rs. 100 a quintal and on Robusta Rs. 60 and now Robusta is raised to Rs. 160 a quintal from Rs. 60. There were representations from all over the country for reducing this. Sir, a cruel joke has been played on this. The total quantity of these lower grades of coffee comes to 50,000 tonnes. Out of this, 15 to 18 thousand tonnes is consumed in the country, on which excise duty was enhanced. When this representation was made, they have shown a great reduction of Rs. 25 per quintal on Excelsia and Liberia coffee only and left out conveniently Robusta which is the major low grade coffee in India. Out of the total production, only 100 tonnes of low grade coffee is Excelsia and Liberica. They have reduced duty on that. It was put on paper that excise duty reduction has been made on lower grades of coffee but the major portion that is Robusta, is left out completely. I do not know whether it was deliberately done or it was by mistake. I would request the hon. Minister to look into this, and if they really are interested in showing relief to consumers by way of reducing enhanced rates of excise duty, they should do it on Robusta coffee and not on Liberica and Excelsia which are only 100 tonnes out of 50,000 tonnes of the lower grade coffee produced in India. I understand that the Finance Minister had promised to look into this when the Finance Bill was discussed. I would request the hon. Minister to look into this. If it is not deliberate, I would like it to be reviewed and and reduced. But if it is deliberate, then this is a very cruel joke, because the relief which you propose to give on 100 tonnes only is negligible. I would rather say that you need not do it at all.

Sir, then I would like to refer to one other subject; that is about the States' overdrafts. My friend, Mr. Viswanath Menon has already referred to it. Recently, in the first week of this month, there was a furore in Karnataka and Kerala States when their cheques were bounced; the Reserve Bank had refused to honour the cheques of the State Governments because the overdrafts have not been brought down. Here, one point has to be very carefully looked into. The States which were in deficit at the end of the month of March that is the previous financial years have to cover the deficit, and in the month of April there will be a spill-over of expenditure from the month of March, and there will be increased overdrafts as a result of the combined impact of these measures. If the Central Government, instead of taking up with the State Governments, this critical situation in the month of April and tried to adjust out of the ways and means advance or the sharable portions of central duty, and straightaway asks the Reserve Bank to hold up the cheques, it is most embarrassing situation to the States. If this sort of thing continues, the Centre-State relations will become very bad. I understand that both the Finance Minister of Kerala and Karnataka had to come to Delhi and to go from pillar to post to get the clearance. When the Central Government is prepared to consider ways and means advances and also sharable portions of the estate duty, why don't they do it beforehand? Why do they make the States run about?

There is a talk of federal and unitary system. Now the States more or less are something like alien States. Every State has its own 'Bhavan' in Delhi and has a special Commissioner, who has to go and chase the files in the Central Secretariat. What sort of thing is this? If there is a better Centre-State relationship, why should there be this? Before Independence, every native state had its own representative in

[Shri U. K Lakshmana Gowda.]

Delhi. And the same situation continues today. Every State has got its Special Commissioner in Delhi. What are they doing here? They are here as liaison men to pull the strings now and then. This situation should be remedied as soon as possible. I think this is one of the reasons why the Tamil Nadu Government has come out with the Rajamannar Committee Report. I fully support the view that there should be a greater autonomy for the States, at least in the case of resources mobilisation and this sort of friction should be eliminated as quickly as possible. (*Time Bell rings.*)

Sir, some references were made about urban and rural areas. We have to consider that 80 percent of the population lives in the rural areas and 20 percent of the population in the urban areas. Nobody can deny that the power of the Government at present whether it is one political party or the other party, vests in the urban section and not in the rural section. Of course, the rural sections provide the votes whereas the urban sections provide funds for the election campaign. This has been the situation. Any agitation, whether it is a labour agitation or an agitation on some other matter, political or otherwise comes from the organised section in the urban sector. For example, even separate *per capita* incom efigures are not available for the rural population. With all the land legislations and others coming in, we do not correctly know how many own less than 5 acres of land in the whole country. Even in 1964-65, when the first land was ceiling legislation moved the idea was that a net income of 3600 rupees is quite enough for a family. Even when the land ceiling laws were revised and the ceiling limit was reduced, it was felt that the agricultural sector had made certain increases in output because of inputs and technology and, therefore, the income per acre and family had gone up. What to say about the fall in the value of the rupee? They are where they were years ago. Their ceiling for agriculture is 3600 rupees net in crore per year. But what about ceiling on urban property? It may be 5 lakhs. I am not saying that you should have a urban ceiling and you should cut a building into six pieces and make each piece worth one lakh of rupees. The urban ceiling is supposed to be 5 lakhs of rupees. Urban property ceiling is a hoax and some farce of a legislation will be passed but it will never be implemented. Therefore, the actual effect will be that if there is any ceiling on the ownership of the means of production, it will be on the 80 per cent of the population that is rural population only. People talk about landlords and kulaks but where are they after your implementation of the land legislations and after you put the land legislations in the 9th Schedule barring them from the judicial review? You will give the urban people a ceiling limit of 5 lakh whereas for the rural people, it will be 10 acres or 15 acres of land. It is just for the satisfaction of the rural people that you are proposing a ceiling on the urban people. What I am saying is that more funds should be available for the development of rural areas.

(*Time bell rings*)

One minute more, Sir. I won't take long. Another problem is that ours is a country with low agricultural production. We have 80 per cent of the people living on agriculture whereas in many other advanced countries, that population has been reduced to 6-10 per cent. In the United States, only 6 per cent of the people are working on agriculture and even then they are feeding their entire population and supply the surplus to rest of the world. Rural people migrate to urban areas. Actually, there should be more migrations to reduce pressure on agriculture. You must syphon off the surplus population from the agricultural area to other spheres industries and small scale industries. You should develop small industries, distribute them over small urban areas. Then only you can reduce the pressure on the land and make the agricultural economy profitable. Otherwise, we will be producing

hordes of 2-acre and 3-acre people, who will be having only a subsistence-living, and they will not be able to produce enough to meet their own demands let alone and providing for the non-agricultural community as surplus. This is the main difficulty at present. Everybody talks about the rural wealth going up. The other day, the Planning Minister said that so much of inputs have gone in, and that bigger farmers have benefited. What is the total number of bigger farmers who might have been benefited? I would urge here that in the devolution of tax revenue, greater share should be made available to the States, and in the States, greater share should be made available to the backward areas and also to the agricultural sector. Thank you, Sir.

SHRI G. LAKSHMAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am of the opinion that the Government of India have committed a mistake in appointing a politician as the Chairman of the Finance Commission. When there is a party system of Government in this country, a politician should not have been appointed to that post. Sir, we have a party system here. Mr. Brahmananda Reddy is a Congress leader. And our Government in Tamil Nadu is a D.M.K. Government, a Government of some other party other than Government. When this party system of Governments are in India, this post should not have been given to a politician. Of course, because there was no vacancy at that time in the Cabinet, they wanted to give him this post and then to take him into the Cabinet. Sir, I am saying that as a principle, when the party system of Government is in existence, a political party leader should not be made the Chairman of the Finance Commission. I am saying this because a great injustice has been done to Tamil Nadu. In the grant-in-aid, nothing has been allotted to Tamil Nadu, and so many great injustices have been done. Sir, in our memorandum to the Finance Commission, we had asked that the dearness allowances to be granted to the State Government employees must be given by the Central Government. This has not been considered by the Finance Commission. Of course, I am not asking that the pay of the State Government employees be paid by the Central Government. Sir, who is responsible for the rise in prices in various parts of the country? As you know, Sir, the State Government employees are not able to make both ends meet. Whenever the prices increase, the Central Government is granting dearness allowance to its employees in its ownway. The State Governments are not responsible for the increase in prices. The Central Government alone is responsible because of its fiscal policy. Therefore, the Central Government has got a responsibility to pay the dearness allowances of the State Government employees. And, Sir, this has not been considered by the Finance Commission. And the State Governments have no resources. They cannot tax. Everything is controlled by the Central Government. Sir, after the Pay Commission's recommendations were out, dearness allowance has been granted on four occassions to the Central Government employees. And, Sir, whether he is a Central Government employee or a State Government employee, both of them go to the same market to purchase commodities and the price is the same for both. A State Government employee cannot say, "I am not a Central Government employee Therefore, you must give me brinjals at Rs. 2 a kilo." And they are not able to make both ends meet. And hence they make a noise and they agitate. And the State Governments, with their poor resources, are not able to meet the demands of the State Governments. Therefore, the Finance Commission should have decided that the dearness allowance of the State Government employees should be borne by the Central Government.

Sir, I now come to prohibition. Many hon. Members on the other side are *pakka* Gandhians. They stand by Gandhiji and follow his principles. Of course, we are also the followers of Mahatmaji. We scrapped prohibition first. And, then the

[Shri G. Lakshmanan.]

people thought that scrapping of prohibition was not good. Therefore, our State Government have decided to close today shops at the first stage and introduce prohibition partially and from September onwards this year we are going to close all arrack shops. The other foreign liquor shops will continue and some decision will also be taken about them and finally prohibition will be re-introduced again in Tamil Nadu. Since we lose Rs. 20 to Rs. 30 crores in the revenues, we wanted that the Central Government must come to the rescue of the State Government in meeting this shortfall. Therefore, the Finance Commission has not done anything in this regard. I think that they also want that prohibition should be scrapped. But, I find the Chairman of the Finance Commission always with a Gandhi-cap and, therefore, something ought to have been done to help those States which wanted to implement prohibition. They ought to have been financed by the Central Government. But, it has not been done. That is an injustice done to Tamil Nadu. In spite of all these difficulties we want to introduce prohibition again. However, the State Government is going ahead. They have announced their policy. But, the Central Government should have come to their rescue.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh): How much will they lose?

SHRI G. LAKSHMANAN: They will lose about Rs. 35 crores. Partially we are losing now about Rs. 15 crores. Again from September we may be losing about Rs. 25 crores. When prohibition is introduced fully, we will lose about Rs. 35 to Rs. 40 crores. Anyhow, the Government of Tamil Nadu is very serious in introducing prohibition. But, the Central Government has to come to their rescue.

Then, Sir, the most important problem which has not been dealt with by this Finance Commission is the problem of unemployment in this country. They have not found out any solution to this problem. No State Government can solve this problem because their resources are meagre. Whatever they collect by way of taxes, is spent in paying dearness allowance etc. to the State Government employees. Therefore, the Finance Commission should have allotted some crores of rupees to the State Government for solving this unemployment problem. Why was an elected Government in Gujarat ousted? The Central Government thinks that the trouble was only against the State Government. They think that there was some trouble there and hence the people ousted that Government. But, the position is different. It was a show of no confidence against the Central Government also. Since Delhi is far away, they are not able to come here. How many people are unemployed today? The number of unemployed in India is more than those of employed. The Finance Commission should have given a very careful consideration to the solution of this problem and should have allotted Rs. 100 to 200 crores to each state to solve unemployment on the basis of population. The Finance Commission should have acted in such a manner, Sir But the Finance Commission has miserably failed.

Lastly, Sir, you know that there are a number of public undertakings controlled by the Government of India. These undertaking are spread throughout India and they are functioning as separate monarchs. Our State Government wanted that they also must be associated with the Salem Steel Plant, which is controlled by the Government of India. A heavy loss running into some crores of rupees has been shown by this public undertaking Who is responsible for it? All these things you may consider Sir. The State Governments have no say in the functioning of public undertakings. The Chief Minister of Tamil Nadu cannot go to the I.C.F. and without sending a chit he cannot see the General Manager. The General Manager may even refuse admission. Therefore, if losses in public undertakings have to be met, the State Governments must be associated with them and then only public undertakings can actually function in a profitable way.

4 P. M.

Therefore, I am also placing this suggestion before you for your consideration. With regard to Tamil Nadu I may tell you it has been neglected. Even in the 'Grant-in-Aid' etc., it has been neglected and, therefore, I submit these things for your consideration. I would be very much thankful if the hon. Minister gives a reply to those issues which I have raised.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : To curtail speeches in the Third Reading, I would suggest that the Members who have given names for the Third Reading may take the opportunity in the First Reading itself, to make it easy for the passing of the Bills. Yes, Mr. Kunjachen.

SHRI P. K. KUNJACHEN (Kerala) : While moving the Bills here the Minister has stated that the Government has accepted the recommendations of the Sixth Finance Commission into to. But when the Sixth Finance Commission was appointed, a memorandum was submitted from our Party-side a memorandum was also submitted by the Kerala Government before the Finance Commission. I am sorry to state that we have not been satisfied by the decision of the Finance Commission. Not only that even though it directly does not come under the purview of the Finance Commission we have also submitted an outline of the alternative policies to be followed in the Fifth Five Year Plan but no comments have been made on that also.

Sir, at present 20 per cent of the total tax collected is being set apart for distribution to the States, out of this 75 per cent depending upon the population and 25 cent on considering the backwardness. I am really sorry to state that the portion set apart for the States is very meagre and we are of the opinion that at least 75 per cent of the total collection—I agree with Mr. Viswantha Menon—should be set apart for distribution to the States; otherwise the States will be put into so much difficulties.

The Centre-State relations in terms of the Constitution of India are supposed to be ceased on federal principles but in reality, however, they are more unitary than federal. In the very division of functions between the Centre and the States, the Constitution has been biased towards Centre. Furthermore, as the Constitution has come to be worked out in practice the Centre is increasingly encroaching upon the rights and power of the States. Now the States are finding it very difficult.

[**Mr. Deputy Chairman** in the Chair].

The States will approach the Central Government and they will talk of the financial difficulties of the States and the Centre will tell the States about the difficulties of the Central Government. Both will say that they are very much in difficulty. What is the reason for this? The reason is, till the Government is following a pro-capitalist, a promonopolistic, a pro-landlord policy, till the Government is not prepared to change its policies, the Government is not going to get out of this crisis. Depending upon the present system itself, something has to be done to save the States. More autonomy should be given to the States. Otherwise, the States will be put into to much difficulty.

Last week, the Finance Minister from Kerala came over to Delhi because in Kerala all the cheques issued by the State Government have been disowned by the Reserve Bank. In Kerala they have not been able to pay the salaries to the Government employees. That is why the Finance Minister, the Finance Secretary and some other officers came from Kerala to Delhi. They had a discussion with the Union Finance Minister, with the Prime Minister and after discussions it has been decided to adjust the overdraft at present. And a party is going to Kerala to conduct an on-the-study, it is understood. Only after that, decisions will be taken finally.

[Shri P. K. KUNJACHEN.]

The position is that for the Government of India, Nasik Press is there. They can print notes and resort to deficit financing. Also the Government is at liberty to raise loans either internally or externally, that is, from other countries. But the States' resources are very meagre. There is no ground for further taxation and they cannot raise internal loans also. Therefore, they are more and more resorting to overdraft which the Central Government is denying to them saying that they should not cross the limit of overdraft. Therefore, we are put into much difficulties. A solution must be found for that.

I wish to bring to the notice of the Government some other things also. Sir, now the 'sons of the soil' theory is spreading from one State to another State. It is spreading throughout India. If this 'sons of the soil' theory is adopted as was advocated by somebody, will it solve the unemployment problem? I feel that the unemployment problem will not be solved in any State. Only some clashes and some disturbances can be created. Unemployment problem cannot be solved by creating this theory. For that, something else has to be done. The country should be industrialised. For that, there should be a separate planning. Here I wish to bring to the notice of the Government some of the peculiarities of the Kerala State. Sir, my friend stated here about the industrial backwardness of the Kerala State. Now, which are the industries at present in Kerala? Most people are employed in the traditional industries, like coir and handloom and cashew nuts. The coir industry is in crisis; the cashew industry is in crisis and the handloom industry is in crisis now. So the people of Kerala are suffering so much. A large number of persons are employed in the coir industry, in the cashew industry and in the weaving industry. No big industries are there. The Central Government has neglected Kerala in the matter of big industries.

Similarly regarding the field of agriculture also, we are producing commercial crops and from those commercial crops, the Government of India is earning foreign exchange to the tune of Rs. 150 crores. It is not possible to convert the commercial crop into other cultivation like paddy cultivation etc. So we are short of rice; we are short of wheat and other things. Supply from the Central Government is very meagre. We are short of everything.

Educated unemployment problem is a serious problem with us as well as the population. Even though our State is a very small State, we have got 4 per cent of the total population of India but allotment from the Centre is below 4 per cent.

Another point: natural calamity is taken as one of the aspects of backwardness. The entire coast of Kerala is eroded by sea. Sea erosion is not taken as a natural calamity. My point is that sea erosion must be taken as a natural calamity while considering backwardness of a State, and on that basis something should be done.

It is reported in the Press that 6 M.L.As. from the Muslim League have withdrawn their support to the Government. So in Kerala there is only a minority Government. How many days they will continue I do not know they have no right to continue in power. The six M.L.A.s have withdrawn their support to the Government but yet the Government carries on. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You must speak about excise duties.

SHRI P. K. KUNJACHEN: I know you will try to purchase the Kerala M.L.As in order to continue in power. But I say they have no moral right to continue. So far as Kerala is concerned, it is the duty of the Central Government to see that the financial position of Kerala is taken into account and something is done to improve the situation.

With these words I conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am told instead of third reading Members will speak now itself. Mr. Barman.

SHRI B. D. BARMAN (Tripura): These Bills which we are considering relate to the distribution of the money collected as excise duties. Distribution of money carries with it as a corollary the utilisation thereof. Unless the money is utilised properly distribution would mean nothing. So distribution of money carries with it the idea that the money must be utilised for the purpose for which it is distributed and this utilisation carries with it the implication of planning according to which this money could be utilised. So my first criticism so far as the Sixth Finance Commission's recommendation is concerned is that this allocation of money or distribution of money must be under a planned economy. The concept that this allocation has to be on population basis and backwardness is a misnomer. India is a developing country; it cannot be said that India is a developed country; so the backwardness is there in every State. The question is only the degree of backwardness. So we have really to see what is the need of each State. Only with a proper plan you can decide what each State needs. Of course backwardness of the State should have priority consideration in the matter of allocation of money because when we consider the body as a whole, if a part of the body is crippled we cannot have a good body unless the part which is crippled is removed. Similarly if we want to have India as a whole developed, if we want to build a socialist India we must try to see that these backward States, relatively backward States are brought on par with others. Then we can think of the progress of socialist India as a whole Otherwise the allocation of moneys in terms of population is a misnomer. These big cities have grown as a sign of exploitation of the British imperialists. They have created these big cities because they wanted to exploit the resources of our country. Most people rush to the cities because they will get many amenities in the cities. Naturally the population in the big cities will be necessarily more in comparison with the villages and other States where there are no big cities. So this allocation of money in terms of population is a misnomer. There must be a plan and we should find out what is the need of each State and money should be distributed according to the needs of each State. We have also to see that the money is utilised properly; not a farthing of it is to be misused. So in order to have distribution of money there must be a plannned economy and unless and until there is a planned economy the future of this country will be dark.

Mr. Deputy Chairman, Sir, in this context I will be failing in my duty if I do not say something about Tripura.

At first glance it might appear that Tripura is having a share three times more than it was before, but this is not the real picture. Tripura was a Union territory and only in 1971 it became a full-fledged State. I must say when Tripura was a Union territory the responsibility lay with the Union Government for its improvement, but Tripura is the most neglected of all the States. Its strategic importance is very well known. When the Bangladesh trouble started, the name of Tripura appeared on the front page of newspapers. You just opened the newspaper at that time every day you found Tripura being mentioned. This is because it is surrounded almost on all sides by East Pakistan, now Bangladesh. Tripura has got no industry at all. Up till now so much planning has been done, but it has got no industry at all. If we ask why it is so, they say there is no communication. When we ask why there is no communication, they say there is no industry. This is arguing in a circle. Why is there no communication and why is there no industry? Who has put this obstacle in the way of the industrialisation of Tripura? Tripura is rich in its resources. It is a jute-producing State. Tripura is rich in forest produce. There are plenty of bamboos in Tripura. It can be utilised for making paper and newsprint. Tripura is rich

[Shri B. D Barman]

in mineral resources, but I am extremely sorry to say that Tripura has got no assistance for all this planning. The money allocated for Tripura was all utilised as remuneration for the wellfed officers deputed there. I must say because of its strategic importance, more allocation should be made to the State of Tripura, so that India as a whole and India as a nation may flourish. All backward States should be enabled to come on a par with the other States. So, I think this distribution of taxes is unscientific. It must be based on the needs of each State. There must be proper planning and a proper assessment of the actual needs of the States. As a result, there will be growth not only of each State, but of India as a whole, a socialist India of which we can be proud.

श्री राजनारायण : (उत्तर प्रदेश) : उप-सभापति जी, यह जो समय समय पर केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध सुधारने के लिए सरकार व्यवस्था करती रहती है, मेरी दृष्टि से वह नाकाफी है। सरकार चाहे संघीय उत्पादन शुल्क बिल लाये, चाहे अतिरिक्त उत्पादन शुल्क बिल लाये और चाहे सम्पदा शुल्क बिल लाये, इस तरह से किसी को 17 प्रतिशत, किसी को 10 प्रतिशत और किसी को कुछ प्रतिशत देकर वह समस्या का समाधान नहीं कर सकती है।

श्रीमन्, यहां पर कांग्रेस की ओर से दो वक्ता बोले है। एक तो श्री जगदीश जोशी बोले है और दूसरे श्री कल्पनाथ राय बोले है। तो यदि कल्पनाथ जी की स्पीच मान ली जाय, कांग्रेस सरकार उसको कार्यान्वित करे तो हमको आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि कल्पनाथ राय ने जितनी अपने शब्दो मे कांग्रेस सरकार की भर्त्सना की है 25 साल के शासन की शायद मैं उन शब्दो में न कर पाऊं, मुझमे क्षमता नहीं है। जगदीश जोशी भी वहां गए है। अच्छा है कि अभी तक हमारा असर इन पर है। करीब 20 साल की राजनीति में डा० लोहिया के चरणो में रह कर उसको वे याद कर ले रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वे इस सदन में बोल कर ही न रह जाएं बल्कि कांग्रेस पार्टी में अपना उतना प्रभाव कर लें कि जो वे यहा बोल रहे है उसके मुताबिक कांग्रेस सरकार अपनी योजना बनाए।

मै अब आ रहा हू कि हमारा यह संविधान फेडरल, साधिक है या नहीं है और अगर साधिक है तो इसका क्या स्वरूप होना चाहिए। मेरा कहना यह है कि नाम मे तो यह साधिक है, लेकिन काम मे यूनीटरी है। अब कुछ कोट करना चाहूंगा--

"Under our Constitution. . . ".

श्री काली मुखर्जी : हिन्दी मे बोलो।

श्री राजनारायण . यह उद्धरण है। यह किताब मुझे तमिलनाडु सरकार ने दी है, मैं इसको फाड़ूंगा नहीं क्योंकि मैं तमिलनाडु सरकार की इज्जत करता हू। क्यों इज्जत करता हूं, यह मैं बाद मे बताऊंगा।

श्री नवल किशोर . एक्साइज ड्यूटी में वह कहा से आ गई ।

श्री राजनारायण : मैं कोट कर रहा हूं .—

"According to Sir Robert Garran. "Federation is a form of Government in which sovereignty or political power is divided between the Central and State Governments so that each of them within its own sphere is independent of the other". Professor Wheare defines the federal principle thus : "By the federal principle I mean the method of dividing powers so that the general and regional governments are each, within a sphere co-ordinate and independent."

"A federal State derives is very existence from the Constitution. Hence, any power, legislative, executive or judicial, whether it belongs to the Centre or to the individual States, is subordinate to and controlled by the Constitution" "(Dicey's Laws of the Constitution)".

ये तीन कोटेशन हमने यहा पर दिए । अगर फेडरल का अर्थ लोगों ने समझा हो तो केन्द्र अपनी सीमा में आजाद रहे, राज्य सरकारें अपनी सीमा में आजाद रहे।

श्री काली मुखर्जी: मिस्टर डिप्टी, चेयरमैन इस का कोई रेलेवेन्स है ?

श्री राजनारायण . काली बाबू को इतना भी समझ नही आया। यह कर का बटवारा है। केन्द्र जो चाहे कर का बटवारा करे . .

श्री काली मखर्जी : इसका रेलवेस क्या है ?

श्री रबी राय : आप जोर से बोलिए।

श्री राजनारायण मै जोर से नही बोलूंगा, मुझको दूसरी मीटिंग मे जाना है।

श्री गुणानन्द ठाकुर . फाइनेन्स कमीशन राष्ट्रपति जी बराबर बैठाते है और वह सारे देश का दौरा करके अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, तो उस पर नेता जी को क्या आपत्ति है ?

श्री काली मुखर्जी यह दूसरा चेला है ?

श्री राजनारायण यह थोडे दिन ही हमारे साथ रहा, उसके बाद उधर चला गया। मै गुणानन्द को और सदन के सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता कि सांघिक ढांचा तो क्या होना चाहिए। आज हमारा कास्टीट्यूशन अपने नाम को सार्थक नहीं कर रहा है। क्योंकि एक मर्तबा सारी सत्ता केन्द्र में सन्निहित हो जाती है और फिर केन्द्र सारी सत्ता को डेलीगेट करता है, उसका बटवारा करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसलिए इसको कहा जाय कि सांघिक ढांचा है, यह सांघिक शब्द के साथ बलात्कार है।

श्रीमन्, चाहे कोई कमीशन हो, चाहे किसी कमेटी की रपट हो, चाहे राज कमेटी की रिपोर्ट हो, मै यह चाहता हू कि हमारे देश का एक ऐसा संविधान बने जो पूर्ण-रूपेण चौखम्भा राज्य के सिद्धान्त आधारित हो। डा० रा० मनोहर लोहिया ने इस देश को एक देन दी। देश की गरीब जनता का दुर्भाग्य है कि डा० लोहिया द्वारा दिये गये सिद्धान्त और कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा लागू नहीं किये गये। यही कारण है कि भारत दिन प्रति दिन गर्त मे गिरता जा रहा है। डा० लोहिया ने शुरू में बताया कि चौखम्भा राज्य बने। केन्द्र पचायत राज, सूबा पचायत राज, फिर जिला पंचायत राज और फिर गाव पचायत राज। पहले गाव पंचायत राज बने, इसके बाद जिला पंचायत राज बने, इसके बाद सूबा पंचायत राज बने और फिर केन्द्र पंचायत राज बने। मै जानना चाहता हूं उन भाई के लालों से जो कहते हैं कि हम गार्धवादी है, जो कहते है कि हम गाधी जी के सिद्धान्त पर चलना चाहते है, गाधी जी ने जो किताब लिखी है 'हिन्द स्वराज' उसका अध्ययन करें, उसमे गाधी जी ने यही कहा है कि गावों को सम्पन्न बनाओ। अंग्रेजो ने गावो के राज के सिद्धान्त को खत्म किया। यही हमारी दुर्दशा का एक कारण है। हमारे गाव अगर हम प्राचीन पद्धति को देखे तो अपने मे पूर्ण थे हमारी सारी की सारी इसान की आवश्यकता की चीजे उस गांव में प्राप्त थी। अब नही है। इसलिए गाव पचायत राज, जिला पचायत राज, सूबा पचायत राज और केन्द्र पचायत राज होना चाहिए . आज राज ढांचा दो खम्भो पर टिका है--two pillars of the State--सो भी एक पिलर बहुत ही कमजोर है और एक पिलर बहुत ही मजबूत है। केन्द्र का पिलर सबसे मजबूत है, सर्वशक्तिमान है और राज का पिलर बहुत कमजोर नौकरशाही के शासन मे वह नगण्य बन गया है। जब चाहे जिस राज्य को भग कर दो। जिस मुख्य मत्री को अपदस्थ कर दो। श्रीमन्, मै आपसे अदब से कहना चाहता हूं कि केन्द्र के पास जितना धन है चाहे वह किसी भी ड्यूटी के नाम से आता हो, चाहे वह ऐक्साईज ड्यूटी के नाम से आये चाहे वह ऐस्टेट ड्यूटी के नाम से आये, चाहे वह ऐडीशनल ऐक्साइज ड्यूटी के नाम से आये, सारा का सारा धन जितना भर स्टेट के पास है, मै चाहता हूं कि चारापायो पर बांट दिया जाए। केन्द्र के पास केवल विदेशी मामला रहे, सुरक्षा रहे, यातायात रहे, अतर-प्रान्तीय मामले रहे। इसके बाद केन्द्र के पास कुछ नही रहना चाहिए। दिल्ली मे बैठकर योजना मत्री श्री धर यह नहीं बता सकते कि वाराणसी का कौन सा क्षेत्र इस समय नहर खोदने के लिए उपयुक्त है। मै जानता हूं कि जितनी नहरे ऐसी जगहों पर खोद दी गई दिल्ली मे बैठे बैठे मत्रियो के आदेश पर कि सारे के सारे गाव डूब गये क्योंकि वह जगह थी ही नही। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जो देशभक्त है, जो देश की जनता की तरक्की चाहते है तो आज केन्द्र सर्वग्रास्ती मनोवृत्ति लेकर सारा कोष अपने हाथ मे लेती जा रही है, उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाय वरना आज गुलामी की प्रवृत्ति हमारे देश में बढ़ती चली जाएगी। क्यों राज्य अपने मे स्वय सम्पन्न न हो ? क्यों राज्य का कारबार राज्य के द्वारा सचालित न हो ?

[श्री राजनारायण]

जिले की योजनायें चले और वह जिले द्वारा संचालित क्यों न हो? गाव की योजनायें चलें और वह गाव के द्वारा सचालित क्यो न हो। आज गाव पचायत नाम मात्र की चीज रह गयी है। उस के पास कोई अधिकार नही हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब चाहे उस गांव पंचायत को तोड़ दे। इसी तरह राज्य सरकार जब चाहे जिला पंचायत को तोड़ दे, केन्द्र की सरकार जब चाहे राज्य सरकार को तोड़ दे। यह स्थिति जनतंत्र का मखौल है, तमाशा है। इस लिए मैं अपने मित्र नवल किशोर जी से कहना चाहता हूं कि वह एक जगह बैठ कर कायदे से इन तमाम बातों को हृदयंगम करें। कभी कभी बातों को वह इधर उधर बिखेर देते है जिस से वह काम नही पाती। क्या कारण है कि यह कहा जाता है कि हमारा मुल्क आजाद है पिछले 25 साल से, 27 साल से, लेकिन यह आजादी है या गुलामी है।

Freedom is the recognition of necessities. From the realm of necessities to the realm of freedom.

SHRI NIREN GHOSH : He has quoted Engels.

SHRI RAJNARAIN: Yes, I have quoted Engels.

यह आजादी की परिभाषा है। जब मनुष्य अपनी विवशता से निकल कर स्वच्छंद वातावरण में विचरण करे तो कहा जाता है कि वह आजाद है। हम दिन प्रति दिन अपनी मुसीबतों में जकड़े जा रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा नही कर पा रहे है। हम को विवशतायें घेरे जा रही है और कहा जाता है कि हम आजाद हैं। इस लिए मै बहुत ही अदब से माननीय से कहूंगा कि माननीय, यह जो बंटवारा इस में किया गया है इस बटवारे से काम चलने वाला नही है। शुद्ध चौखम्भा राज्य बनाओ। जो राजकोश हो उस का चौथाई धन केन्द्र का है, चौथाई स्टेट ले, चौथाई जिला ले और चौथा गाव ले और राज्य सरकार चलाने वालों से निवेदन करना चाहता हू कि वह भी सोचें। खास तौर से तमिलनाडु के बारे में कहना चाहता हूं कि वह भी अगर तमिलनाडु चाहता है कि वह आजाद रहे तो पहले तमिलनाडु अपने जिले को आजादी क्यों नही देता और जिला गाव को आजादी क्यों नही देता। यह दो खम्भा राज्य नही चलेगा, चार खम्भा राज्य चलेगा तभी जा कर देश की स्थिति सुधरेगी और तभी देश की जनता आप की योजनाओं में अपने को साझीदारी बना पायेगी। वरना यह आप की योजनायें कागज पर ही धरी रह जायेगी। मैं एक बात और सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि या तो गांधी जी का नाम लेना बन्द हो या फिर इस देश में शराब बद हो। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, 1930, 1932 में शराब की दुकानों पर पिकेटिंग करते थे। उत्तर प्रदेश के आकड़े मुझे याद है। 1942 में 3 लाख गैलन शराब सरकारी दुकानो से कहा बिकती थी और आज वहा 56 लाख गैलन शराब उत्तर प्रदेश मे सरकारी दुकानों पर बिक रही है। पहले की 18 गुनी। तो शराब पिला कर जो सरकार अपने राज कोश को बढ़ाये गांधी जी के शब्दों में वह सरकार पाजी सरकार पापी न है। अंग्रेजी सरकार के लिए गाधी जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया है पाजी और पापी। इसलिए गांधी जी के शब्दों का ही मै प्रयोग कर रहा हूं कि यह सरकार पाजी है और यह सरकार पापी है। (**व्यवधान**) और अगर देखा जाय, वह माननीय सदस्य मुसलमान हों तो कुरान पढ़ते होंगे। उत्तर प्रदेश की हर जेल में हम ने कुरान की किताब रखवा दी है। मुसलमानों के लिए कुरान में शराब छूना तक हराम बनाया गया है न। यहां बहुत से मुसलमान कांग्रेस में पड़े हुए है। मैं उन से पूछता हूं कि तुम कांग्रेस में क्यों पड़े हो। ऐसी सरकार में, ऐसे दल में, क्यो पड़े हो कि जो शराब के जरिए सरकारी खजाने को भरता है। तो यह सारी चीजे है उन को समझो। चौखम्भा राज्य चलाओ, देश को बचाओ, भारत को ताकत दो और अपनी ताकत को लगा कर समाज को नष्ट मत करो। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमान्, आप की आज्ञा से बैठता हू और अब मैं यहा से चला जाऊ तो ही अच्छा है।

उप सभापति : अब नीरेन घोष जी बोल रहे हैं।

श्री गुणानन्द ठाकुर : वाक आऊट क्यो कर रहे हैं?

श्री राजनारायण : जा रहे हैं वह शक्ति पैदा करने जो कांग्रेस सरकार को समाप्त कर दे।

SHRI NIREN GHOSH (West Bengal): Sir, I would like to tell the House how the Government has pumped more than Rs. 1,000 crores, perhaps Rs. 2,000 crores, into the pockets of the textile big business tycoons. That is what briefly I want to tell the House.

In 1949 export duty on cotton textile goods was reduced from 20 per cent to 10 per cent and thereafter abolished, and full protection was given, hundred per cent protection was given. In 1966 cotton textile exports—70 per cent of the FOB value in general and 90 per cent in certain varieties have been subsidised by the Government. It is not earning foreign exchange, it is losing foreign exchange. It is subsidised to this huge margin. Then in 1967 there was devaluation. The rupee value fell by 67 per cent. Then they said subsidy was no longer necessary. Thereafter Manubhai Shah became the Commerce Minister. And the whole thing, even after rupee devaluation, has been put into force again. By 1970 subsidy to the cotton textile exports—exports are made by big business houses—exceeded the total subsidy that was given to the cotton textile industry up to the devaluation of rupee in 1967, in three years. Where are the sources for this subsidy to the big business tycoons? The Government exchequer, Foreign Market Development Fund—that is also a Government Fund—levy on imported raw cotton at the rate of Rs. 500 per bale imposed last year. After that, since this entire amount has gone down, imports have been a bit reduced. So it has been made up. Now I give a figure. If Rs. 90 crores worth of cotton textile goods are exported, Rs. 60 crores are subsidised from these sources. That is the position. If you export Rs. 90 crores, Mr. Ranbir Singh, you are giving from your pocket Rs. 60 crores to them. That is how it has been made up. So, that is a policy which is scandalous, scurrilous, totally anti-Indian, at the cost of the people of this country, at the cost of the Government exchequer and at the cost of the foreign exchange resources of the country. This is the sordid state of affairs as regards the cotton textile industry. Only some points I have raised. If the entire issue is raised, then it will become too big perhaps for her to understand. I do not know whether she knows about it.

Now I will touch one or two other points. The point which has been raised here, I want to put it into sharp focus. It is about revenues. Nehru was saying that India should be a free Union of the peoples of India. Mark the words "peoples of India". That is, India is a multi-national State. It is not a uni-national State. For example, A. G. Kulkarni by nationality is a Maharashtrian or a Marathi. By citizenship he is an Indian. That is the position in India. That is a multi-national State. But what is the present position? Our States are nationality based States. What is the financial position of these States? All the financial levers have been concentrated in the hands of the Union Government. But benefits that ought to be given to the people, the social burdens—education, relief, this, that, everything—those are the responsibility of the nationality-based States.

They have been given the responsibilities to give benefits to the people. Those are not the responsibilities of the Government of India. But all the resources have been taken away and these are nationality based States. In any country, union takes places voluntarily and division of powers takes place voluntarily. I say there should be a thorough redistribution of power levers enshrined in the Constitution in favour of the States. The Constitutional amendment must take place to that effect immediately. Pending that, of course, 75 per cent of the revenue and the capital budget must be earmarked to the States and it should be given in accordance with the needs of the State and not in a discriminatory way.

Therefore, I feel that the debts of the States to the Centre should be written off. It has become a huge thing. These should be written off immediately. The States can

[Shri Niren Ghosh]

no longer bear these debts and they cannot go on giving interest on these to the Centre.

Therefore, I would require a Constitutional amendment and a conference for these drastic reforms relating to the financial powers of the Centre and the States. These have become imperative and urgent necessities. I suppose peoples of all the States are deeply interested in these.

In this connection I will say one thing more. Last time I said it. The four crores of rupees of tax evaded by Mundhra could be recovered. A document was with me. Shri K. R. Ganesh has taken that document from me. It has given some photostat copies and the concerns operated by Mundhra in the United Kingdom. All the details are there. It was taken from me by Shri K. R. Ganesh. I would like to know from the Government what steps the Government propose to take to recover these Rs. 4 crores of tax due from Mundhra. This can be recovered. Dummy Directors who are Englishmen are there and assets are there. They are operating these companies in the United Kingdom. It is a huge scandal. The whole Parliament rocked when Shri Feroze Gandhi talked about Mundhra scandal. But unfortunately, Government of India does not do anything in a big way. Jessops has gone. The deposits have gone to U.K. He is now operating four companies, big companies with dummy Directors. Assets are there. You can take the tax due from him. But you are not doing it. Ex-Auditor General, Supreme Court Judges, ex-Ministers and Cabinet Ministers are all involved and they are on the pay roll of Mundhra even now. That is what the document says. I would like the Government to take up the matter seriously.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : Mr. Deputy Chairman, I would like to thank all the hon. Members who have participated in the discussion and I must admit that I have come out wiser after this debate which lasted for nearly four hours.

I had expected that this being quite a limited subject in a way the hon. Members would normally confine themselves to the economic issues. But I find that there was hardly any subject which was not discussed here. It was like the budget discussions where people can take up any subject under the blue or grey sky. I think there was hardly any subject which was not touched upon. I would like in that connection to congratulate them for their very fertile imagination and great power of eloquence with that. I would also congratulate some hon. Members for their maiden speeches. I can appreciate their enthusiasm because of which they came out with many of the things. And probably they did not mean all what they have said because maiden speeches normally carry the first impression of the areas from which they come.

Sir, I wish the honourable Members had concentrated only on those points. But, Sir, before I go to the economic aspects, I would like to touch upon some of the political points that were raised by some of the party members who have preferred to stay out at this particular juncture. The honourable Member from the BKD, with whom I had the pleasure and privilege of working in the UP Assembly some years ago. I think, utilised this for making a tirade against some parties today and made it a sort of platform for making election speeches. But, since he has said certain things, I would also like to place it on record that this was neither the time nor was it a very desirable thing to say those things from many points of view. But I would not go into the political controversies. I would only say that certain points which have been raised had better been left untouched. For instance, he had touched upon the difference between the rural and the urban sectors, between the villagers and the city people, and he also tried to bring in the issue of differences between the States and the Centre and so

on. This point also has been touched upon by others not only from the point of view of how much money should have gone to which States, but also from the point of view of touching the very core of the federal structure of the Constitution and this bitterness need not have been injected into the debate. There were other Members also who brought in the element of monopolistic system, the entire structure of the monopolies and the private and public sector projects in the country and so on. Then, there was also the point, as the very learned Member, Shri Ghosh, has just now mentioned, about Mundhra and I do not know howfar that was relevant here. But all these issues have cropped up here and I do not think I have really to go into all those details. But on one point I would certainly like to say. The honourable Member from the BKD said that it is the false policies and incorrect policies pursued by the Government that are responsible for certain things. I would categorically deny that. Our policies have been subjected to the public gaze and to test not once, but five times, and each time they have been approved and much of the success which we have received shows that the public stands by our policy. May be that in the implementation of these policies we have not succeeded fully and may be there are certain defects there. But our policies have proved to be correct by and large and even in the recent elections in U.P., from where he is coming, and in certain elections thereafter, the results show to a greater degree that our policies have proved to be the correct policies. If I may go by the report in the Press today according to which somebody from his own party, in his own State has withdrawn in favour of the Congressman, that only shows that the policies of the Congress have by and large been correct.

Sir, some of the points made are really very very unfortunate. Some Members have asked whether there was any close liaison between the Finance Commission and the Planning Commission. The very fact that one of the Members of the Planning Commission was also a Member of the Finance Commission and that there were meetings and opinions were taken into account shows that there was close co-ordination and liaison between them and that the two Commissions have worked in close liaison.

Another point that was raised by an honourable Member on the other side was whether the Chairman of the Finance Commission was the right choice. I can only say, with all the humility at my command and with greater conviction, that the work that was done by this Commission—not that I am belittling the importance of the contributions made by the earlier Finance Commissions—which was chaired by Shri Brahmananda Reddy is very good and important and this Commission had made some very important contributions and it has broken new ground and they have been welcomed not just by one or two states, but also by the State from which he comes and by the entire country. The country as a whole has welcomed many of the recommendations of this particular Commission.

Then, Sir, there is one point which has been raised by many honourable Members and that is a correct point also and that is about the backwardness of certain States. I think, Sir, I can share the anguish and pain of the honourable Members because I also happen to be coming from a very backward State, the State of U.P. though culturally and ethically and religiously and historically U.P. is a very rich State. But economically it is a backward State. . .

AN HON. MEMBER : Most backward.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Well, I do not know whether it is the most backward. But, definitely, we are not the highest and that is obvious. So, Sir, I share the torture and pain which has prompted many of the honourable Members here to say so many things here. But, Sir, I

[Shrimati Sushila Rohatgi.]

would like to touch upon some of the achievements and, in this context, the recommendations of the Sixth Finance Commission in this particular direction. Sir, normally, more populous States are also backward like Bihar and U. P. and certain others and we all know that.

In the allocation of income-tax, the weightage of population has been fixed at 90 per cent. I think that was a point which was raised by one of the hon. Members. So 90 per cent has been taken into consideration. The basis for distribution of Excise Duties is 75 per cent on population and 25 per cent on Backwardness. The weightage for backwardness recommended by the earlier Commission was 20 per cent. And this has been raised to 25 per cent and, therefore, this is a tilt in favour of the States which are backward.

The needs of less advanced States to reach all States average in social service has been recognized and States have been allowed provisions for reaching all-States average in areas like Welfare of Scheduled Castes and Tribes, etc. All matters have been taken into consideration. This provision was also made in the other Plan, but here we find that there is a great improvement on the schemes. As I said earlier special attention has been paid to the problem of backwardness.

One hon. Member—I think it was Mr. Nawal Kishore—referred to the question of emoluments of Government employees. The Commission has allowed full provision for the requirements of States on the basis of scales of pay and allowances as obtaining on 1-1-1972 and has made additional provision to cover the increases from 1-1-1972 to 1-5-1973 on the basis of certain objective norms in regard to the level of emoluments in various States. Now, this point will also be apreciated. This has also been taken into consideration by the Finance Commission. And this was one of the reasons why, we find, that in spite of the fact that report of the Commission was tabled in both the Houses on 1-8-72, we did not receive even any amendment or anything at that time. I mean that no quetions were raised in this House and all the States had been satisfied. And it is for the first time that there has been no representation against the recommendation of the Commission. That speaks volumes for the work done by the Commission as a whole.

One point raised both by some Member from the Treasury Benches and the Members from the opposite—I think that is a correct point too—was about the mechanism. I would like only to say that the Sixth Finance Commission has provided about Rs. 816 crores to 15 States for upgradation of standards of administration of which about Rs. 457 crores are in respect of Uttar Pradesh and Bihar. I am just trying to mention this because these two particular States have been mentioned earlier. About the mechanism, the Commission, therefore, Sir, has made certain suggestions :

> "We consider primary education, medical and public health and welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes to be of critical importance for the well-being of the people and particularly the weaker sections. We have, therefore, thought it essential to devise suitable special safeguards against diversion of the funds so provided for improvement of these services to other purposes .... we cannot over-emphasize the need for effective and purposeful monitering of the special grains earmarked for administrative upgradation.
>
> "To this end, we make an important suggestion. The concerned administrative Ministry at the Centre and the Planning Commission should, as part of their Scrutiny of the Annual Plans of the States, take special care to verify whether the funds provided by us for primary education, medical and public health and welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward

clases have been utilise don these services. We would suggest that only such expenditure on these services as is in excess of the provisions indicated by us under these heads, should alone be treated as Plan expenditure. . . We hope that with this safeguard the special funds we are now allocating as part of grants-in-aid for improvement of social services, will not run the risk of being diverted to other heads.".

These suggestions have been accepted by the Government.

Now, Sir, some points have been raised by the hon. Members coming from Kerala. They have referred to a number of questions like bouncing, etc. These were discussed at the time of the Finance Bill also. Particularly, they have spoken about the allocation and a particular percentage which should have been or could have been increased. Some States including Kerala had also requested for an increase in the State share.

SHRI SHYAM LAL YADAV : On a point of order, Sir. My point is that Madam has just now said—

वी०के०डी० ने हमारी नीतियो का समर्थन किया और विजनौर में अपना उम्मीदवार वापस ले लिया यह बात गलत है। विजनौर में हमारा कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया गया। किसी ने नामज़दगी करने के बाद ही वापस ले लिया। हमारी तरफ से कोई अधिकृत उम्मीदवार नही था और है किसी को हमने अपनी सहमति दी, न किसी का नाम ऐनाउंस किया। यह बात सर्वथा गलत है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I think the Minister will take care of it.

श्री कल्पनाथ : श्रीमन्, विजनौर में इनका उम्मीदवार था। ये झूठ बोलते हैं।

श्री श्यामलाल यादव : मैं पार्टी का जनरल सक्रेटरी हूं, मैं जानता हूं। आप यह नहीं कह सकते है।

श्री उप-सभापति : आप बैठ जाइये।

श्री श्यामलाल यादव : कल्पनाथ जी ने कहा ये झूठ बोलते है, ऐसी बात इनको नही कहनी चाहिए. . .

श्री उप-सभापति आप बैठ जाइये।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Sir, he is a very senior Member for whom I have the greatest respect. Probably he did not hear what I said. I would ask him kindly to get the verbatim of what I have said. If I remember aright, I said on the basis of the report of the Press. I also said, "whatever the thing was, whether it was discretion or valour. . . " You kindly get it and check it for yourself. I have nothing against the person or the party.

SHRI SHYAM LAL YADAV : I have explained it. I hope she must accept my version.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : She made a statement and explained that it was on the basis of Press reports. There the matter ends.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : We were talking about Kerala just now. As I said earlier, they had asked for a larger share or increase in the State share of the excise duty from 20 per cent to 50 per cent. The Commission has taken all these things into account and it was thought that it would stick to the 20 per cent average as in the case of other States also. Sir, unfortunately, Kerala and Karnataka States have been facing some trouble for some time past and therefore, on a number of occasions a number of steps have also been taken so that the problems of these two States could also be sorted out. Sir, I would like to make only one correction. It would not be correct to say that the suspension of the payment by the Reserve Bank of India came all of a sudden. That would not be correct and, therefore, I would like to correct this information also.

There was another point raised about the grants-in-aid to Kerala. I would only like to place on record that the grants-in-aid to Kerala would be 209 crores of

[Shrimati Sushila Rohatgi]

rupees under the Sixth Commission's recommendation. It stood at 50 crores of rupees under the Fifth Commission's recommendation. So the difference can be seen from the figures. The grant-in-aid to Kerala is lower only than Assam, Orissa, Rajasthan and West Bengal. Kerala State is also being given a debt relief of 110 crores of rupees. It is not correct to say that we do not try to understand the difficulties of the States. Of course, Kerala is a very lovely and a very picturesque State. It is a highly educated State also. We understand the difficulties and the problems of unemployed engineers and others that have mentioned. But from the point of view of record, I would like to say that it has not received less. In fact, it has received a substantial sum more than the last time.

Sir, there is another point which I would like to say about the total picture as it emerges out of the Sixth Finance Commission. If we followed the same criteria as were accepted in the Fifth

5 P.M.

Finance Commission, the States would have received today Rs. 6,872 crores, out of the taxes and duties. But we find now that according to the pattern and formula and the criteria of the Sixth Finance Commission, the transfer works out to Rs. 7,099 crores. And, therefore, that shows an increase of Rs. 227 crores. The grant-in-aid also amounted to Rs. 711 crores during the Fourth Plan, whereas according to the Sixth Finance Commission, we find that it works out to Rs. 2,510 crores. That also shows a difference between the two Commissions. And the transfers to the States have substantially increased. By and large, the States have also, as far as I think, been satisfied. Moreover, the debt rescheduling is of the order of Rs. 2,000 crores. This has been liberalized and this will be some relief to the States and they welcomed this.

Sir, I would like to take this opportunity to ask and appeal to the hon. Members here that it is not only the devolution which is going to help the States but we expect that they are partners in this. And more resources have also to be built up by the States. And, Sir, for resources mobilization, for example, there is the National Savings Scheme. The States have, by and large, welcomed this process because two-thirds of these savings go to the States, and, therefore, there is another avenue for this. And I will agree with the hon. Members that at this time of economic crisis, of inflation and when the people are facing so many difficulties, there is ample scope, whether it be at the Centre or in the States, for saving, for economy, for austerity, for changing our habits and our way of life, and for economic discipline. All these factors are there. I think, with this, the hon. Members will agree with me that the allegation that there has been discrimination is not correct. As a matter of fact, before I sit down, I seek your permission, Sir, to quote a few figures about a few other States.

Sir, one of the hon. Members has mentioned earlier also about Madhya Pradesh. In regard to Madhya Pradesh, according to the last Commission, the transfer was to the tune of Rs. 343.10 crores. After the recommendations of the Sixth Finance Commission, it works out to Rs. 543.57 crores. And I have already quoted in regard to Kerala. As regards to Bihar—I don't think the hon. Member is present now—it got Rs. 508.73 crores after the Fifth Finance Commission, whereas after the Sixth Finance Commission's recommendations, it will come to Rs. 844.72 crores. And this not in any way to say that this enough or this is sufficient to meet all the requirements. I agree with the hon. Members. But the fact lies that the question of any discrimination does not exist here. In fact, for those States which are behind the all-India average, efforts will be made through devolution and through these various steps that they come nearer the All-India average. And I am sure, the hon. Members would have been convinced and they would not have any objection to pass this. With these words, Sir I commend the Bills.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now I will put the motion.

The question is :

"That the Bill further to amend the Union Duties of Excise (Distribution) Act, 1962, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Sir, I move :

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now I will put the motion.

The question is :

"That the Bill further to amend the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Sir, I move :

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now I will put the motion.

The question is :

"That the Bill further to amend the Estate Duty (Distribution) Act, 1962, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, to Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS LAWS (AMENDMENT) BILL, 1973.

Motion for Reference to Joint Committee

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI) : Sir, with your permission I move the following motion :

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do join in the Joint Committee of the Houses on the Bill further to amend the Industrial Development Bank of India Act, 1964, the Reserve Bank of India Act, 1934, the Industrial Finance Corporation Act, 1948, The State Financial Corporations Act 1951, the Life Insurance Corporation Act, 1956 and the Unit Trust of India Act,